website: www.royalpatrika.com
G-mail: royalpatrika@gmail.com
Yahoo: royal_patrika@yahoo.com

R.N.I. No. RAJHIN/2012/48736

दैनिक
रॉयल पत्रिका

वर्ष : 14 | अंक : 07 | पेज: 8 | जयपुर, गुरुवार 18 दिसम्बर 2025 | मूल्य: 1.50 रुपये

इथियोपिया की संसद को संबोधित कर रहे पीएम मोदी

-सर्वोच्च सम्मान के लिए जताया आभार, भारत-इथियोपिया रिश्तों को बताया मजबूत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार, 17 दिसंबर को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने इथियोपिया सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और इथियोपिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत और स्थायी संबंधों का प्रतीक है। सम्मान ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इथियोपिया को 'लैंड ऑफ लायंस' बताया और कहा कि उनका गृह राज्य गुजरात भी शेरों का घर है, इसलिए उन्हें यहां आकर घर जैसा ही महसूस हो रहा है।

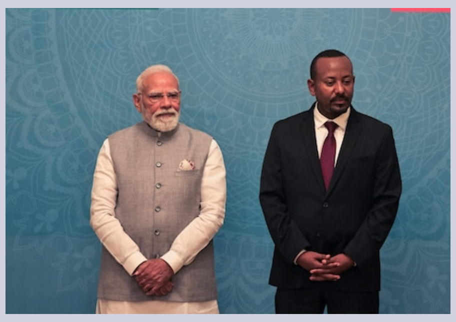

पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद में भाषण देते हुए कहा कि आज इस प्रतिष्ठित सदन के सामने खड़ा होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, "इथियोपिया, लैंड ऑफ लायंस में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यहां गहरा अपनापन महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों के लिए जाना जाता है।" पीएम मोदी ने दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया की सभ्यताएं प्राचीन हैं और उनके मूल्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यहां आना उनके लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह भारत के 140 करोड़ लोगों का संदेश लेकर इथियोपिया आए हैं।

सर्वोच्च सम्मान मिलने पर क्या बोले पीएम मोदी?

इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने पर पीएम मोदी ने इसे भारत के लोगों की ओर से विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि इथियोपिया आज इसलिए प्रगति कर रहा है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं और वह भविष्य को खुले दिल से अपनाने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी अपनी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए आधुनिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग और मित्रता को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला:

20 और देशों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध, फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी सूची में शामिल

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यात्रा और आव्रजन नीति को और सख्त करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत 20 और देशों के नागरिकों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले से अमेरिका आने वाले पर्यटकों और स्थायी रूप से बसने की कोशिश करने वालों, दोनों पर कड़े प्रतिबंध लागू हो गए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, अब कुल पांच देशों के नागरिकों पर अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है, जबकि 15 देशों के नागरिकों पर आंशिक रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

सुरक्षा कारणों का दिया हवाला

सरकार ने बताया कि हाल ही में व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड जवानों पर गोलीबारी के आरोपी एक अफगान नागरिक की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं को और मजबूत किया। अधिकारियों का कहना है कि कई देशों में सरकारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता संदिग्ध है, अपराध से जुड़े रिकॉर्ड सही तरीके से उपलब्ध नहीं होते और इससे यात्रियों की पृष्ठभूमि जांच कठिन हो जाती है। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि कुछ देशों में भ्रष्टाचार, राजनीतिक

अस्थिरता और कमजोर शासन व्यवस्था सुरक्षा, विदेश नीति और आव्रजन से जुड़े जोखिम बढ़ाती है। इसके अलावा, कई देशों के नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं, और कुछ देश अपने नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर देते हैं।

किन देशों पर पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध

मंगलवार को प्रशासन ने बुर्किना फासो, माली, नाइजर, दक्षिण सूडान और सीरिया को पूर्ण प्रतिबंध सूची में शामिल किया। दक्षिण सूडान पहले से ही कड़े प्रतिबंधों में था। आंशिक प्रतिबंध की सूची में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंज़ानिया, टोंगा, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे को जोड़ा गया है। इसके अलावा, लाओस और सिएरा लियोन को आंशिक प्रतिबंध से हटाकर पूर्ण प्रतिबंध वाले देशों में डाल दिया गया है, जबकि तुर्कमेनिस्तान पर कुछ ढील दी गई है, क्योंकि वहां सुधारों का हवाला दिया गया है।

कुछ श्रेणियों को राहत

हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास पहले से वैध अमेरिकी वीजा है, उन पर यह रोक लागू नहीं होगी। स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) धारक, राजनयिक, खिलाड़ी और कुछ विशेष श्रेणियों के वीजा धारकों को भी छूट दी गई है। यदि किसी व्यक्ति का प्रवेश अमेरिका के हित में माना गया, तो उसे विशेष अनुमति दी जा सकती है।

पहले भी विवादों में रही नीति

गौरतलब है कि ट्रंप ने जून में पहली बार यात्रा प्रतिबंध लागू किए थे, जब 12 देशों पर पूर्ण और सात देशों पर आंशिक पाबंदी लगाई गई थी। यह नीति उनके पहले कार्यकाल की चर्चित यात्रा प्रतिबंध नीति की याद दिलाती है, जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कानूनी चुनौतियां हुई थीं। समर्थकों का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होती है, जबकि आलोचकों का मानना है कि यह नीति लोगों को उनके देश के आधार पर अनुचित रूप से निशाना बनाती है।

बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का कड़ा पलटवार

-बोले– 'गैरजिम्मेदाराना बयान बर्दाश्त नहीं, भारत चुप नहीं रहेगा'

नई दिल्ली। बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा भारत के खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़ा जवाब दिया है। सीएम सरमा ने मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को कहा कि बांग्लादेश में एक वर्ग लगातार यह कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पड़ोसी देश में मिला दिया जाना चाहिए, जो न सिर्फ गैरजिम्मेदाराना बल्कि बेहद खतरनाक सोच है। उन्होंने साफ कहा कि भारत इस तरह की धमकियों पर चुप नहीं बैठेगा।

हसनत ने दिया था भारत को तोड़ने का बयान

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, बांग्लादेश की एनसीपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नई दिल्ली बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश करती है, तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग करने और वहां अलगाववादी तत्वों को समर्थन देने पर विचार करना चाहिए। हसनत अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था, "अगर भारत उन ताकतों को शरण देता है जो बांग्लादेश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक अधिकारों और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करतीं, तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।" इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक और रणनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।

बांग्लादेश की मानसिकता को जवाब मिलेगा

असम के लुमडिंग में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले एक साल से बांग्लादेश से इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत एक विशाल देश है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश इस तरह की बातें सोच भी कैसे सकता है?" सीएम सरमा ने बांग्लादेश की इस सोच को "नापाक और भ्रामक" करार देते हुए कहा कि ऐसी मानसिकता को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश को दी जाने वाली मदद और सहयोग पर भी गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना चाहिए। हिमंत बिस्वा सरमा ने सख्त लहजे में कहा, "हमें उन्हें यह सबक सिखाना चाहिए कि अगर वे इसी तरह भारत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, तो हम चुप नहीं बैठेंगे।"

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड:

लूथरा ब्रदर्स गोवा लाए गए, पूछताछ से पहले एक ने सीने में दर्द की शिकायत

नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में 6 दिसंबर को हुए भीषण अग्निकांड के मामले में सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से निर्वासित किए जाने के बाद बुधवार (17 दिसंबर 2025) को दिल्ली से गोवा लाया गया। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। गोवा पुलिस की टीम लूथरा बंधुओं को सुबह 10.45 बजे मोपा स्थित मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लेकर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, आग की घटना को लेकर उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। एयरपोर्ट से उतरने के बाद दोनों को शिओलिन मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर ले जाया गया, जहां एक भाई ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चिकित्सकीय जांच और इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपियों को अंजुना पुलिस थाने ले जाया जा सकता है। अग्निकांड के बाद अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। पूछताछ के बाद उन्हें नियमित रिमांड के लिए मापुसा की अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह, आग लगने की घटना के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल का 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया और पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। भारत सरकार के अनुरोध पर 11 दिसंबर को थाई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में निर्वासन की प्रक्रिया पूरी की। इस मामले में गोवा पुलिस पहले ही नाइटक्लब के पांच प्रबंधकों और स्टाफ सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लूथरा बंधुओं की पूछताछ से हादसे के कारणों और सुरक्षा चूक को लेकर कई अहम खुलासों की उम्मीद की जा रही है।

उत्तराखंड सरकार को झटका:

धर्मांतरण कानून पर फिलहाल ब्रेक, राज्यपाल ने लौटाया विधेयक

देहरादून। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान करने वाले धामी सरकार के महत्वाकांक्षी विधेयक पर फिलहाल विराम लग गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी देने के बजाय पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इससे सरकार की उस कोशिश को झटका लगा है, जिसमें गंभीर धर्मांतरण मामलों में उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया था। धामी सरकार ने हाल ही में जबरन धर्मांतरण के मामलों में दंड को और कठोर बनाने के लिए कानून में संशोधन किया था। यह संशोधित विधेयक अगस्त 2025 में गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि, सूत्रों के अनुसार विधेयक के ड्राफ्ट में कुछ तकनीकी और कानूनी खामियां पाई गईं। इन्हीं कारणों से राज्यपाल ने विधेयक पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार से दोबारा विचार करने को कहा है। विधायी विभाग को यह विधेयक मंगलवार को वापस प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अब सरकार के सामने दो रास्ते हैं। पहला, यदि सरकार कानून को जल्द लागू करना चाहती है तो अध्यादेश के जरिए इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि अगले विधानसभा सत्र में संशोधित विधेयक को दोबारा पेश कर पारित कराया जाए और फिर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण से जुड़े कानून को पहले भी सख्त किया जा चुका है। वर्ष 2018 में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया था। इसके बाद 2022 में धामी सरकार ने संशोधन कर सजा के प्रावधानों को और कड़ा किया। इसके बावजूद सरकार का मानना रहा है कि संगठित और

गंभीर मामलों पर लगाम कसने के लिए और सख्त कानून जरूरी हैं। विधेयक 2025 में कई अहम बदलाव प्रस्तावित थे। छल, बल या प्रलोभन से धर्मांतरण कराने पर सजा की अवधि दो से सात साल से बढ़ाकर तीन से दस साल करने का प्रस्ताव था। शिकायत दर्ज कराने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को देने और डीएम को आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने का प्रावधान भी शामिल था। सबसे सख्त प्रावधान विवाह का झांसा, नाबालिगों से जुड़े अपराधों या दुष्कर्म जैसे मामलों में 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का था। अब राज्यपाल के फैसले के बाद सबकी नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी

-'WFH नियम का 100 फीसदी पालन करें, नहीं तो होगी कार्रवाई'

नई दिल्ली। दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार द्वारा लागू किए गए 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम नियम को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पहले ही सरकारी और निजी कार्यालयों में आधी कार्यबल के साथ काम करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस आदेश को दोबारा दोहराते हुए कहा है कि वर्क फ्रॉम होम नियम का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली के सभी सरकारी और निजी विभागों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी कार्यालय में इस नियम का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

फुल वर्कफोर्स के साथ चलेंगे ये विभाग

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि CAQM और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली में 50 फीसदी अटेंडेंस का नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कल से दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानों में केवल आधा स्टाफ ही कार्यालय में उपस्थित रहेगा और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं को इस नियम से बाहर रखा गया है। हेल्थ केयर सेवाएं, अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी कार्यबल के साथ संचालित होती रहेंगी। इसके अलावा

अन्य सभी सरकारी और निजी संस्थानों में यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने आगे कहा कि दिल्ली में इस समय ग्रैप-4 लागू है। ग्रैप-3 के दौरान 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की ओर से 10,000 रुपये सीधे उनके खातों में दिए जाएंगे और ग्रैप-4 समाप्त होने के बाद भी उसी आधार पर सहायता जारी रहेगी।

AAP पर साधा निशाना

बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री कपिल मिश्रा ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर साल प्रदूषण के समय एक महीने की छुट्टी पर क्यों चले जाते थे, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब जब दिल्ली की एक महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ राजनीति कर रही है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी।

विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और इजरायल के बीच तकनीक, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जयशंकर ने लिखा, "आज शाम यरुशलम में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात कर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। तकनीक, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर उनके विचारों को महत्व दिया। मुझे विश्वास है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी।" बैठक के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी X पर पोस्ट किया, "आज शाम मैंने यरुशलम में अपने कार्यालय में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मुलाकात की।" इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से भी

मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत–इजरायल रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने पर चर्चा की। X पर जयशंकर ने लिखा, "आज इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग से मुलाकात कर सम्मानित महसूस किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं। हमारी रणनीतिक साझेदारी और इसे और मजबूत करने पर चर्चा हुई। क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की।" राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने भी जयशंकर से मुलाकात पर खुशी जताते हुए X पर लिखा कि दोनों पक्षों ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, खासतौर पर भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEC) के माध्यम से। इसके अलावा, विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बार्कात से भी मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश और नवाचार सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार किया गया। जयशंकर ने X पर लिखा, "आज यरुशलम में इजरायल के अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री नीर बार्कात से अच्छी बैठक हुई। निवेश और नवाचार सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत-इजरायल मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द पूरा करने को लेकर विश्वास जताया, जिससे आर्थिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।" इजरायल के मंत्री नीर बार्कात ने भी X पर कहा कि उन्हें जयशंकर से मिलकर खुशी हुई। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों ने मुक्त व्यापार समझौते से पहले के फ्रेमवर्क समझौते से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, जिस पर उन्होंने करीब तीन सप्ताह पहले भारत के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि भविष्य को यह समझौता इजरायल के लिए बड़ा बाजार खोलेगा, व्यापार बाधाओं को कम करेगा और इजरायली निर्यात को बढ़ावा देगा।

CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत पर बवाल

-वीडियो वायरल होने के बाद धार्मिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान पर छिड़ी बहस

नई दिल्ली। बिहार में नवनियुक्त आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद यह कार्यक्रम केवल एक प्रशासनिक आयोजन न रहकर राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। मामले को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, महिला सम्मान और व्यक्तिगत सहमति जैसे गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित किया गया था, जहां एक हजार से अधिक आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। इसी दौरान मंच पर हुई एक घटना ने पूरे आयोजन की दिशा बदल दी।

महिला आयुष चिकित्सक से जुड़ा मामला

वायरल वीडियो के अनुसार, नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची एक महिला आयुष चिकित्सक, जिनका नाम नुसरत परवीन बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री के सामने खड़ी थीं। वीडियो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कथित तौर पर उनके चेहरे की ओर इशारा करते हुए हाथ बढ़ाते दिखाई देते हैं, जिसके दौरान महिला का हिजाब हटता हुआ नजर आता है। इस क्षण में महिला चिकित्सक असहज दिखती हैं। हालांकि यह एक औपचारिक सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद इस घटना को महिला की व्यक्तिगत गरिमा और धार्मिक आस्था से जोड़कर

देखा जाने लगा।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई लोगों ने मुख्यमंत्री के व्यवहार को अनुचित बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की। यूजर्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक पहचान और निजी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, विशेषकर सार्वजनिक मंच पर। मामले ने मीडिया का भी ध्यान खींचा और पाकिस्तान के प्रमुख अख़बार डॉन में इस पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में महिला की सहमति का सवाल उठाया गया और बताया गया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे तक की मांग की जा रही है।

पाकिस्तान से आई धमकी और बयान

विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दी। उसने माफी न मांगने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। भारत में इस बयान को उकसावे और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

मानवाधिकार संगठनों की जांच की मांग

इस मामले पर पाकिस्तान के कुछ मानवाधिकार संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद और मानवाधिकार आयोग ने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठनों का कहना है कि यह मामला महिला की गरिमा, धार्मिक स्वतंत्रता और बुनियादी मानवाधिकारों से जुड़ा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि संबंधित महिला चिकित्सक से आधिकारिक माफी मांगी जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं।

रॉयल पत्रिका

संपादकीय....

मनरेगा में बदलाव क्यों? उपलब्धियों, आरोपों और बदलती जरूरतों के बीच सरकार का तर्क

वर्ष 2005 में शुरू हुई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को ग्रामीण भारत के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में देखा गया। इसका मूल उद्देश्य था—ग्रामीण परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार देकर गरीबी, भुखमरी और मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकना। अब सरकार इस योजना के नाम और प्रारूप दोनों में बदलाव की बात कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठे—आखिर ऐसा क्यों और किस आधार पर? सरकार का तर्क है कि बीते दो दशकों में देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। जारी मसौदे और एफएक्यू में कहा गया है कि गरीबी दर 12 वर्षों में 25.7 प्रतिशत से घटकर 4.86 प्रतिशत रह गई है। यदि यह दावा सही माना जाए तो यह संकेत देता है कि जिस व्यापक गरीबी को ध्यान में रखकर मनरेगा की परिकल्पना की गई थी, उसकी तीव्रता अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में सरकार यह मानती है कि योजना को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप ढालना आवश्यक हो गया है। सरकार की दूसरी बड़ी दलील योजना में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ी है। एफएक्यू में पश्चिम बंगाल के 19 जिलों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां बिना काम के भुगतान और फंड के दुरुपयोग के मामले सामने आए। इसके अलावा 2025-26 की मॉनिटरिंग में 23 राज्यों में या तो काम बिल्कुल नहीं हुआ या खर्च स्वीकृत राशि से कम पाया गया। कुल मिलाकर लगभग 193 करोड़ रुपये के मिसएप्रोप्रिएशन की बात कही गई। सरकार के अनुसार, इन खामियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा ढांचा जवाबदेही और प्रभावशीलता के लिहाज से कमजोर है। हालांकि, इस तर्क के दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि औसतन एक लाख करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में 193 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आती है, तो यह कुल खर्च का लगभग 1.93 प्रतिशत ही है। किसी भी बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में इतनी मात्रा को पूरी योजना की विफलता का आधार बनाना कई विशेषज्ञों को उचित नहीं लगता। इसके उलट, मनरेगा ने महिलाओं की भागीदारी को सवा गुना तक बढ़ाया और करीब 12 करोड़ श्रमिकों को काम से जोड़ा—यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कोरोना महामारी के बाद मनरेगा की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हुई। लॉकडाउन के दौरान जब शहरी रोजगार ठप हो गए, तब यही योजना ग्रामीण गरीबों के लिए जीवनरेखा बनी। लाखों प्रवासी मजदूर गांव लौटे और मनरेगा के तहत मिले काम ने उन्हें भुखमरी और पूरी तरह टूट जाने से बचाया। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने भी "द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट" रिपोर्ट में इस योजना को दुनिया की बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गिना। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि मनरेगा गलत हो गई, बल्कि यह है कि सरकार इसे किस दिशा में ले जाना चाहती है। कृषि कार्य के दौरान दो महीने का ब्रेक और कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 125 करना यह संकेत देता है कि सरकार इसे खेती के पूरक के रूप में देखना चाहती है, न कि उसके विकल्प के रूप में।

सार्वजनिक उपक्रमों के दौर की वापसी का संकेत देता इंडिगो संकट, निजी विमानन पर सरकारी दखल ने खड़े किए गंभीर सवाल

-निजी क्षेत्र की सफलता पर संकट, इंडिगो प्रकरण ने सरकार और बाजार के रिश्ते उजागर किए

भारत में आर्थिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्र को जिस भरोसे के साथ आगे बढ़ाया गया था, उसका सबसे चमकदार उदाहरण नागरिक विमानन रहा है। सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस-परमिट राज और सार्वजनिक उपक्रमों की अक्षमताओं से बाहर निकलकर इस सेक्टर ने न सिर्फ तेज़ी से विस्तार किया, बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि अगर सही नीतिगत माहौल मिले तो भारतीय निजी कंपनियां वैश्विक मानकों पर खड़ी हो सकती हैं। इंडिगो इसी कहानी का सबसे बड़ा अध्याय है। लेकिन आज वही इंडिगो संकट के केंद्र में है और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस संकट से निपटने के नाम पर सरकार जिस तरह आगे बढ़ रही है, उससे निजी क्षेत्र की क्षमताओं और स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इंडिगो को लेकर सामने आई घटनाओं पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं और दिलचस्प बात यह है कि तीनों प्रतिक्रियाओं के भीतर एक गहरी हताशा छुपी है। पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि इंडिगो के संस्थापक और उसके शीर्ष प्रबंधक बेहद नासमझ, अदूरदर्शी या अहंकारी रहे होंगे, जिन्होंने इतनी बड़ी और सफल कंपनी को इस हालात तक पहुंचने दिया। दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि जो भी सरकार से, खासकर उस दौर में, टकराव मोल लेने की सोच रहा होगा जब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पर संवेदनशील मेहमान—जैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन—देश में मौजूद हों, वह बड़ी भूल कर रहा है। और तीसरी प्रतिक्रिया उन लोगों की है जो दशकों से यह तर्क देते आए हैं कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र बेहतर सेवा दे सकता है, वहां सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग हैरानी और गुस्से में पूछ सकते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि इस पूरे सिद्धांत को ही उलट कर रख दें? सच्चाई यह है कि भारतीय निजी विमानन

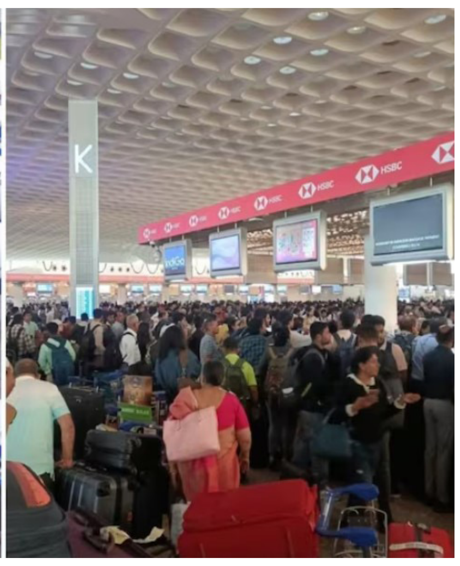

उद्योग ने बीते वर्षों में कई झटके सहे हैं और फिर भी खुद को संभाला है। जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसी बड़ी एयरलाइनों का बिखरना इस सेक्टर के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। इसके बावजूद निजी विमानन ने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा, बल्कि विस्तार भी किया। एअर इंडिया का निजीकरण हुआ और यह एक ऐसा कदम था जिसने साफ संदेश दिया कि सरकार अब कारोबारी संचालन से बाहर निकलना चाहती है। उस वक्त पुरानी हुकूमत के कई लोग अपनी 'सत्ता' छिन जाने से खिन्न थे, क्योंकि अब सरकारी खजाने से विमान खरीदने, नौकरियां बांटने, ठेके देने और उपभोग की चीजों की खरीद का सिलसिला थम गया था। एक मायने में सरकार को कम-से-कम एक बड़े सेक्टर में अप्रासंगिक बना दिया गया था। निजी विमानन की यह सफलता ऐसी थी, जिससे दुनिया ईर्ष्या कर सकती थी। टेलीकॉम सेक्टर में आज भी सरकार के पास कुछ पुराने अधिकारों के अवशेष मौजूद हैं—स्पेक्ट्रम की नीलामी, बीएसएनएल के रूप में एक सक्रिय सार्वजनिक उपक्रम और वोडाफोन-आइडिया में 49 फीसदी इक्विटी। लेकिन नागरिक विमानन में सरकार के हाथ में महत्वहीन हेलीकॉप्टर चार्टर सेवाओं के सिवा कुछ नहीं बचा है। लगभग सभी बड़े और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट निजी हाथों में जा चुके हैं और जो बचे हैं, वे भी जल्द ही उसी राह पर हैं। यानी यह सेक्टर लगभग पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार एक बार फिर इस सेक्टर में 'वापसी' कर रही है—और वह भी बेहद आक्रामक अंदाज़ में। इंडिगो संकट के दौरान जिस तरह से केंद्रीय मंत्री टीवी चैनलों पर एक के बाद एक इंटरव्यू देते नजर आए, उससे यह संदेश गया कि सरकार न सिर्फ हालात पर नजर रखे हुए है, बल्कि सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने को भी तैयार है। मंत्री जी ने न सिर्फ संकट को दुरुस्त करने के वादे किए, बल्कि परोक्ष रूप से उन सूचीबद्ध कंपनियों के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की बात भी कही, जिनका संयुक्त बाजार मूल्य लगभग 2 लाख करोड़ रुपये यानी करीब 24 अरब डॉलर है। यह अपने आप में हैरान करने वाला दृश्य था। निजी कंपनियों में अगर घालमेल होता है, तो आमतौर पर उसका जवाबदेह सीईओ या बोर्ड होता है। लेकिन यहां ऐसा लग रहा था मानो एक मंत्री खुद सीईओ की भूमिका निभा रहे हों। मंत्री ने खुले तौर पर सीईओ की छुट्टी कर देने की बात कही और उसे सेक्टर के रेगुलेटर के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया। यह सब ऐसे समय में हुआ, जब कंपनी पहले से ही दबाव में थी और बाजार में अनिश्चितता का माहौल था। इस पूरी प्रक्रिया में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया, जब इंडिगो के सीईओ ने पायलटों के काम के घंटों से जुड़े उन नियमों को वापस ले लिया, जिन्हें लागू करवाने में केंद्रीय मंत्रालय और रेगुलेटर पिछले दो वर्षों से नाकाम रहे थे। यानी जो काम सरकार और उसका नियामक तंत्र नहीं कर पाया, वह एक निजी कंपनी के प्रबंधन ने दबाव में आकर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने फरवरी 2026 तक अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती करने का ऐलान किया। यह फैसला यात्रियों के लिए भी झटका था और बाजार के लिए भी। इसी बीच मंत्री की ओर से यह बयान भी आया कि 'डुओपोली' यानी दो कंपनियों का वर्चस्व किसी भी सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता। उनका कहना था कि वे चाहते हैं कि देश में कम-से-कम पांच एयरलाइंस हों और हर एक के पास 100-100 विमान हों। सुनने में यह विचार आकर्षक लग सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बाजार की वास्तविकता भी इसकी इजाजत देती है? क्या सरकार यह तय करेगी कि कितनी कंपनियां होंगी और उनके पास कितने विमान होंगे? यहां तुलना अमेरिका के 'बेबी बेल्स' वाले दौर से की जाने लगी। एक समय अमेरिका में एटीएंडटी के एकाधिकार को तोड़कर उसे कई 'रीजनल बेल ऑपरेटिंग' कंपनियों में बांट दिया गया था। लेकिन उस ऐतिहासिक फैसले के पीछे एक लंबी कानूनी और नीतिगत प्रक्रिया थी, जिसका मकसद प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था, न कि किसी सफल कंपनी को सजा देना। अगर इस प्रसंग की सही जानकारी ली जाती, तो शायद मौजूदा हालात को समझने में मदद मिलती। मंत्री अपने स्टाफ से एक साधारण गूगल सर्च करवा लेते, तो भी यह फर्क साफ हो जाता। भारतीय विमानन बाहर से भले ही विशाल दिखता हो, लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई कहीं ज्यादा जटिल है। यह एक अत्यधिक पूंजी-प्रधान उद्योग है, जहां मुनाफे के मार्जिन बेहद कम होते हैं और जोखिम बहुत ज्यादा। इंडिगो की ही मिसाल लें। उसने 1400 से ज्यादा नए विमानों की खरीद के ऑर्डर दिए हैं। यह ऑर्डर सिर्फ कंपनी के विस्तार की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह भी बताते हैं कि उसे आने वाले दशकों में भारतीय बाजार की मांग पर कितना भरोसा है। लेकिन ऐसे फैसले स्थिर नीतिगत माहौल और नियामकीय भरोसे पर टिके होते हैं। अगर कंपनियों को यह डर सताने लगे कि किसी भी संकट में सरकार सीधे उनके प्रबंधन में दखल दे सकती है, तो निवेश और विस्तार के फैसले प्रभावित होना तय है। सवाल यह भी है कि अगर यह सब सार्वजनिक उपक्रमों वाले पुराने दौर में होता, तो क्या तस्वीर अलग होती? शायद हां। उस दौर में किसी बड़े संकट पर जिम्मेदार अधिकारियों की छुट्टी हो जाती, फाइलों पर नोटिंग होती, जांच कमेटियां बनतीं और अंततः मामला ठंडे बस्ते में चला जाता। आज निजी क्षेत्र से यह उम्मीद की जाती है कि वह ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा पेशेवर और ज्यादा कुशल होगा। लेकिन जब संकट आता है, तो वही पुराना सरकारी अंदाज़ लौट आता है—फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाने पर निजी कंपनियां हैं।

यह पूरा घटनाक्रम भारत के आर्थिक सुधारों की मूल भावना पर भी सवाल खड़ा करता है। सुधारों का मकसद था कि सरकार नीति बनाए, नियम तय करे और नियामक के जरिए निगरानी रखे, न कि खुद कारोबारी फैसलों में उतर जाए। अगर सरकार यह तय करने लगे कि किस कंपनी का सीईओ रहेगा और किसे हटाया जाएगा, तो फिर बोर्ड, शेयरहोल्डर्स और बाजार की भूमिका क्या रह जाएगी? इंडिगो संकट को सिर्फ एक कंपनी की समस्या के रूप में देखना भूल होगी। यह दरअसल उस नाजुक संतुलन की परीक्षा है, जो भारत में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच पिछले तीन दशकों में बना है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है, तो असर सिर्फ विमानन पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उन तमाम सेक्टरों पर पड़ेगा जहां निजी निवेश सरकार के भरोसे टिका है।

लिंक वेस्ट से एक्ट वेस्ट नीति तक भारत की पश्चिम एशिया रणनीति और क्षेत्र में बढ़ती स्थायी कूटनीतिक मौजूदगी

-मोदी की यात्राओं से बदली दिशा, ऊर्जा से आगे रणनीतिक संतुलन और भरोसेमंद साझेदारी का नया अध्याय

पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्तों में एक नया दौर आकार ले रहा है। यह दौर केवल औपचारिक कूटनीतिक यात्राओं या प्रतीकात्मक बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि निरंतर सहभागिता, बहु-आयामी सहयोग और दीर्घकालिक रणनीतिक मौजूदगी की ओर बढ़ता हुआ कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान और जॉर्डन यात्रा इस बदलते रुख की ताज़ा मिसाल है। इन यात्राओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब पश्चिम एशिया को केवल ऊर्जा आपूर्ति या प्रवासी भारतीयों की कमाई तक सीमित नहीं देखता, बल्कि इसे अपनी विदेश नीति के एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में स्थापित कर चुका है।

पश्चिम एशिया और भारत: पुराना रिश्ता, सीमित दृष्टि

आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारत के पश्चिम एशिया से संबंध अपेक्षाकृत संकुचित दायरे में रहे। तेल आयात भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों भारतीय प्रवासी विदेशी मुद्रा का एक अहम स्रोत बने। इस आर्थिक निर्भरता ने संबंधों को व्यावहारिक तो बनाया, लेकिन रणनीतिक गहराई नहीं दी। इज़राइल के साथ संबंध घरेलू राजनीति और फिलिस्तीन मुद्दे के कारण लंबे समय तक सतर्कता और झिझक में रहे। दूसरी ओर, अरब देशों के साथ रिश्ते भी मुख्यतः ऊर्जा सुरक्षा और श्रम बाजार तक सीमित रहे। प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं कम होती थीं और उच्च स्तरीय संवाद में निरंतरता का अभाव दिखता था।

'लिंक वेस्ट' नीति: एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की पश्चिम एशिया नीति में निर्णायक बदलाव आया। 'लुक वेस्ट' से आगे बढ़ते हुए 'लिंक वेस्ट' नीति ने इस क्षेत्र को भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में ला खड़ा किया। इसका मतलब था—सिर्फ देखना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से जुड़ना; सिर्फ आर्थिक रिश्ते नहीं, बल्कि सुरक्षा, राजनीति, संस्कृति और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना।

इस नीति के तहत ऐतिहासिक यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ। सऊदी अरब: 40 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई): 34 वर्षों बाद ईरान: 15 वर्षों बाद: इन यात्राओं ने संदेश दिया कि भारत पश्चिम एशिया को अब केवल "ज़रूरत का साझेदार" नहीं, बल्कि "रणनीतिक सहयोगी" मानता है।

'एक्ट वेस्ट' पॉलिसी: निरंतरता और ठोस परिणाम

'लिंक वेस्ट' नीति की अगली कड़ी के रूप में भारत ने धीरे-धीरे 'एक्ट वेस्ट' पॉलिसी को आकार देना शुरू किया। इसका अर्थ है—सिर्फ संबंध जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें लगातार मजबूत करना और ठोस नतीजों में बदलना।

ओमान और जॉर्डन की हालिया यात्राएं इसी सोच का विस्तार हैं। ये देश भले ही वैश्विक राजनीति में महाशक्ति न हों, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार मार्गों, सुरक्षा सहयोग और कूटनीतिक संतुलन में इनकी भूमिका अहम है। भारत ने यह समझ लिया है कि पश्चिम एशिया में स्थायी मौजूदगी के लिए केवल बड़े देशों से संबंध पर्याप्त नहीं होंगे। छोटे और मध्यम आकार के देशों के साथ भरोसेमंद साझेदारी बनाना भी उतना ही ज़रूरी है।

प्रवासी भारतीय: संबंधों की असली रीढ़

पश्चिम एशिया में करीब 90 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। ये प्रवासी समुदाय भारत और मेज़बान देशों के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। पहले इन प्रवासियों को केवल रेमिटेंस के स्रोत के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब भारत की नीति में बदलाव आया है। सरकार ने उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को कूटनीतिक एजेंडे का अहम हिस्सा बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओं में प्रवासी भारतीयों से संवाद, श्रम समझौतों में सुधार और संकट के समय त्वरित सहायता (जैसे कोविड-19 के दौरान 'वंदे भारत मिशन') ने भारत की विश्वसनीयता को मजबूत किया है। इससे पश्चिम एशियाई देशों में यह संदेश गया कि भारत अपने लोगों के प्रति ज़िम्मेदार है और साझेदारी को गंभीरता से लेता है।

ऊर्जा से आगे: व्यापार, निवेश और तकनीक

तेल और गैस अब भी भारत-पश्चिम एशिया संबंधों का महत्वपूर्ण आधार हैं, लेकिन तस्वीर अब कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। यूएई और सऊदी अरब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल टेक्नोलॉजी मं निवेश बढ़ा रहे हैं। ओमान और जॉर्डन के साथ भी लॉजिस्टिक्स, पोर्ट डेवलपमेंट, खाद्य सुरक्षा और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं बढ़ी हैं। भारत की कोशिश है कि वह पश्चिम एशिया को केवल कच्चे तेल का स्रोत नहीं, बल्कि आर्थिक साझेदारी का मजबूत मंच बनाए।

इज़राइल और फिलिस्तीन: संतुलन की कूटनीति

पश्चिम एशिया की राजनीति इज़राइल-फिलिस्तीन संघर्ष के बिना अधूरी है। भारत ने इस जटिल मुद्दे पर संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाया है। 2018 में रामल्ला की यात्रा ने फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के प्रति भारत के समर्थन को स्पष्ट किया। वहीं, इज़राइल के साथ रक्षा, कृषि और तकनीक के क्षेत्र में गहरे रिश्ते बनाए रखे गए। गाजा संकट के दौरान भारत ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की, साथ ही मानवीय सहायता और शांति पहल का समर्थन भी किया। यह दोहरा रुख भारत की भू-राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है—न तो किसी पक्ष को पूरी तरह अलग-थलग करना, न ही सिद्धांतों से समझौता करना।

क्षेत्रीय संघर्ष और भारत की भूमिका

पश्चिम एशिया आज भी संघर्षों और अस्थिरता से घिरा है—सीरिया, यमन, इज़राइल-गाजा तनाव, ईरान-अमेरिका खींचतान। इन परिस्थितियों में भारत ने खुद को एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत किसी सैन्य गठजोड़ का हिस्सा बने बिना संवाद, कूटनीति और विकास आधारित सहयोग पर ज़ोर देता है।

नाम बदलने की राजनीति में उलझा रोज़गार का सवाल, जब 100 दिन की गारंटी भी ज़मीन पर पूरी नहीं हो पा रही

-मनरेगा का नाम बदले, दिन बढ़े, लेकिन मज़दूर आज भी पूरे काम और भरोसे से वंचित

नाम बदलने की राजनीति कोई नई बात नहीं है। दुनिया के लगभग हर देश में, हर दौर में, सत्ता में बैठे लोग नामों के साथ प्रयोग करते रहे हैं। मुल्कों के नाम बदले गए, शहरों के नाम बदले गए, सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों और योजनाओं तक के नाम बदले जाते रहे हैं। नाम बदलना कई बार इतिहास से मुक्ति का प्रतीक बताया गया, तो कई बार सांस्कृतिक पहचान की वापसी का दावा किया गया। भारत भी इस प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा है। एक दौर था जब नाम बदलने के पीछे एक ठोस तर्क दिया गया। कहा गया कि औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ों ने स्थानीय परम्पराओं, भाषाओं और उच्चारणों को नज़रअंदाज़ कर अपने मुताबिक नाम रख दिए। आज़ादी के बाद उन नामों को बदलकर स्थानीय पहचान लौटाई जा रही है। इसी तर्क के तहत बॉम्बे को मुम्बई किया गया, मद्रास चेन्नई बना, कलकत्ता को कोलकाता कहा गया। कर्ज़न रोड कस्तूरबा गांधी मार्ग बना और किंग्सवे राजपथ कहलाया। इन बदलावों से बहुत लोगों को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इनके पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक न्याय का भाव दिखता था। हालांकि, यह भी सच है कि नाम केवल सरकारी गज़ट से नहीं बदलते। वे लोगों की जुबान, उनकी याददाश्त और रोज़मर्रा की बोली में बसते हैं। इसलिए कनॉट प्लेस आज भी कनॉट प्लेस है, भले ही काग़ज़ों में वह राजीव गांधी चौक कहलाता हो। नाम बदल देने से स्मृति नहीं बदल जाती। लेकिन बीते कुछ वर्षों में नाम बदलने की जो मुहिम तेज़ हुई है, वह पहले वाली कोशिशों से अलग नज़र आती है। अब यह सिर्फ़ औपनिवेशिक विरासत को हटाने या स्थानीय पहचान को लौटाने का मामला नहीं रह गया है। अब इसमें मज़हबी पहचान, सांप्रदायिक आग्रह और एक खास तरह की राजनीति की झलक साफ़ दिखाई देती है। कई जगह यह कोशिश दिखती है कि मुस्लिम नामों, मुस्लिम शासकों या मुस्लिम पहचान से जुड़े संदर्भों को योजनाबद्ध तरीके से हटाया जाए या उन्हें नकारात्मक रूप में पेश किया जाए। दिल्ली की एक प्रमुख सड़क का नाम बदलकर औरंगज़ेब रोड से एपीजे

अब्दुल कलाम मार्ग कर दिया गया। तर्क दिया गया कि हमें औरंगज़ेब जैसे नहीं, कलाम जैसे मुसलमान चाहिए। यह तर्क अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या इतिहास को इस तरह अच्छे और बुरे के खांचे में बाँट देना इतना आसान है? क्या किसी समुदाय की पहचान तय करने का हक़ सत्ता को होना चाहिए? और क्या नाम बदलकर इतिहास से असहमति जताना इतिहास को समझने का सही तरीका है? इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया। यह सच है कि प्रयागराज नाम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है और यह नाम पहले से प्रचलन में भी था। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे नाम भी बदले गए जो आम लोगों की जुबान में रच-बस चुके थे। नए नाम कई बार इतने संस्कृतनिष्ठ और अनजाने होते हैं कि वे लोगों के स्मृति-कोश से मेल ही नहीं खाते। नतीजा यह होता है कि शहर अपने ही लोगों के लिए अजनबी होते चले जाते हैं। नाम बदलने की इस राजनीति का सबसे ताज़ा और शायद सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मनरेगा का प्रस्तावित नाम परिवर्तन है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम। यह योजना सिर्फ़ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों गरीब परिवारों के लिए रोज़गार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी का प्रतीक थी। इसमें महात्मा गांधी का नाम जुड़ा होना केवल एक औपचारिक बात नहीं थी, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक था जिसमें काम को अधिकार माना गया।

कुछ समय पहले यह कहा गया कि मनरेगा का नाम बदलकर 'पूज्य बापू रोज़गार गारंटी योजना' किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर भी बहस हुई, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि इसकी जगह एक बिल्कुल नया नाम चुना गया है— 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)'। हिंदी और अंग्रेज़ी का ऐसा मिला-जुला, बोझिल और उलझाऊ नाम शायद ही आम ग्रामीण की समझ में आए। इस नाम का संक्षिप्त रूप बनता है— वीबी-जी राम जी। यह महज़ संयोग है या इसके पीछे कोई प्रतीकात्मक राजनीति है, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या यह महात्मा गांधी के नाम और उनकी सोच को धीरे-धीरे हाशिए पर डालने की कोशिश है? पहले गांधी की जगह 'पूज्य बापू', फिर एक ऐसे नाम की रचना जो 'राम जी' पर आकर ठहरती है। नामों के इस खेल में मंशा को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोज़गार योजना को एक वैचारिक प्रयोगशाला बना देना ज़रूरी था? लेकिन असली चिंता का विषय नाम नहीं, काम है। नाम बदलने की इस पूरी कवायद में असल मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि नए कानून के तहत रोज़गार गारंटी अब 100 दिन की नहीं, बल्कि 125 दिन की होगी। पहली नज़र में यह बहुत आकर्षक लगता है। ऐसा लगता है जैसे सरकार ने मज़दूरों, दिहाड़ी करने वालों और ग्रामीण गरीबों का ख़ास ख़याल रखा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? शनिवार को 'दैनिक भास्कर' में छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में बताया कि मनरेगा के तहत बीते पांच वर्षों में प्रतिवर्ष औसतन सिर्फ़ 50.24 दिन का ही रोज़गार मिला है। यानी काग़ज़ पर 100 दिन की गारंटी होने के बावजूद आधे से भी कम दिन का काम मिल पा रहा है।

जब 100 दिन की गारंटी ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसे 125 दिन कर देने का क्या मतलब है? यह सवाल बेहद बुनियादी है। क्या सरकार के पास इतना काम नहीं है कि वह लोगों को रोज़गार दे सके? या फिर बजट की कमी है? या फिर प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव है? दूसरी तरफ़ यह भी पूछा जा सकता है कि क्या लोग काम मांग ही नहीं रहे हैं? अगर लोग काम नहीं मांग रहे, तो उसकी वजह क्या है—कम मज़दूरी, भुगतान में देरी, या काम की कठिन शर्तें? इन दोनों ही सूरतों में 125 दिन की गारंटी का दावा खोखला साबित होता है। अगर सरकार रोज़गार दे नहीं पा रही, तो गारंटी बढ़ाने का ऐलान महज़ एक राजनीतिक नारा है। और अगर लोग काम लेने नहीं आ रहे, तो पहले यह समझना ज़रूरी है कि वे क्यों नहीं आ रहे।

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर नागौर में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

-सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में किसान आयोग अध्यक्ष ने जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

-जिला विकास पुस्तिका का भी किया विमोचन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (सूचना केन्द्र) में आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी एवं जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ ही जिले के विकास को प्रदर्शित करने वाली तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी 18 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में राज्य और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास को प्रदर्शित किया गया। 'बदलता राजस्थान' और 'विकसित भारत' की तस्वीर विद्यार्थियों और आमजन के लिए एक जीवंत अनुभव के रूप में सामने आई। किसान आयोग अध्यक्ष व जिला कलक्टर ने उद्घाटन के पश्चात प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों का समग्र प्रदर्शन —

जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए इसकी विषयवस्तु एवं संपूर्ण व्यवस्था की सराहना भी की। जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि "नव उत्थान–नई पहचान, बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान" की भावना को प्रतिबिंबित करती इस प्रदर्शनी को राज्य सरकार की दो वर्षों की उपलब्धियों का सशक्त प्रस्तुतीकरण है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं से व्यापक रूप से अवगत कराते हुए अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान–2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रभावी प्रगति हो सके।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा बहुविभागीय विकास कार्यों की प्रस्तुति —

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता, जल संसाधन, पीएचईडी, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन, श्रम, ऊर्जा, खान एवं भू-विज्ञान, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, वन, पर्यटन सहित अन्य विभागों के विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया

जिला विकास पुस्तिका का विमोचन —

इसी क्रम में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में मुख्य अतिथि किसान आयोग अध्यक्ष श्री सीआर चौधरी व जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि 'जिला विकास पुस्तिका' में जिले में हुए सभी विकास कार्यों, नवाचारों और आगामी योजनाओं का समग्र विवरण शामिल है। यह पुस्तिका आमजन को सरकार की गतिविधियों और योजनाओं से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी। प्रदर्शनी और विमोचन समारोह ने जिले के नागरिकों को सरकारी योजनाओं और विकास की उपलब्धियों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन न केवल जिले के विकास की तस्वीर पेश करता है, बल्कि आमजन और प्रशासन के बीच संवाद का सशक्त माध्यम भी बनता है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि सभी विभाग परस्पर समन्वय एवं संवेदनशीलता के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

राजीविका मुख्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस्थान सरकार के वर्तमान कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) के जयपुर स्थित मुख्यालय में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान का नेतृत्व राजीविका की स्टेट मिशन डायरेक्टर श्रीमती नेहा गिरि द्वारा किया गया। अभियान में विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए कार्यालय परिसर के विभिन्न अनुभागों और कक्षों की गहन साफ-सफाई की, जिससे स्वच्छ, स्वस्थ एवं सकारात्मक कार्य वातावरण का निर्माण हुआ। अभियान के दौरान स्टेट मिशन डायरेक्टर द्वारा प्रत्येक अनुभाग एवं कक्ष का व्यक्तिगत निरीक्षण किया गया। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा किए गए स्वच्छता प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता की सराहना की। इस अवसर पर श्रीमती नेहा गिरि ने कहा कि स्वच्छता केवल विशेष अभियानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे नित्य, साप्ताहिक एवं मासिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निरंतर स्वच्छता प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छता अभियान को वास्तविक रूप से साकार किया जा सकता है। राजीविका परिवार ने इस विशेष अभियान के माध्यम से यह संदेश दिया कि स्वच्छता एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे अपनाकर ही स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है।

सांस्कृतिक संध्या में आमजन ने प्रदेश के गौरवशाली लोक नृत्य और संगीत का लिया आनंद

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जवाहर कला केंद्र, जयपुर में आयोजित की जा रही राज्य सरकार की चार दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 'नव उत्थान, नई पहचान – बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान' के दूसरे दिन मंगलवार को भी बड़ी संख्या में आमजन ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों एवं नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी के दौरान सांस्कृतिक संध्या में आमजन ने नृत्य और लोक गीतों का आनंद लिया—सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर कथक केंद्र की टीम ने प्रस्तुति दी। राजस्थान राज्य के नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य और ममता सपेरा के द्वारा मोरचंग, खड़ताल जैसे वाद्ययंत्रों से लोक कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने जेकेके परिसर में उपस्थित दर्शकों के हृदय को प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव से सराबोर कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में सूचना एवं जनसंपर्क व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य कार्मिक व आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर: सीएसटी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अवैध हुक्का बार–नाइट क्लब पर छापा

-क्लब हब-40 से 24 हुक्का, तम्बाकू सामग्री जब्त, मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार

जयपुर। सी.एस.टी. (क्राइम ब्रांच) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने थाना जवाहर सर्किल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार एवं नाइट क्लबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने गौरव टावर, मालवीय नगर स्थित क्लब हब-40 पर छापा मारते हुए होटल मैनेजर सहित 3 अभियुक्तों को कोटपा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है, जबकि 3 बाउंसरों को धारा 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान क्लब की आड़ में चलाए जा रहे हुक्का बार से 24 हुक्का, 24 पाइप, 24 चिलम, साथ ही 14 डिब्बे तम्बाकू फ्लेवर एवं 8 छोटी डिब्बियां जब्त की गईं। जांच में सामने आया कि क्लब नियमों के विरुद्ध संचालित किया जा रहा था।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई

यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (अपराध) अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (संगठित अपराध) लाल मीणा के निकट सुपरविजन में तथा पुलिस निरीक्षक रतन सिंह कविया (सीएसटी) के नेतृत्व में की गई। सीएसटी टीम ने संभावित अवैध हुक्का बार एवं क्लबों को लेकर सूचना संकलित कर उसे विकसित किया, जिसके बाद थाना जवाहर सर्किल (जयपुर पूर्व) में यह कार्रवाई अंजाम दी गई।

प्रकरण दर्ज, 24 व्यक्तियों के चालान

इस संबंध में पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जिला जयपुर (पूर्व) में प्रकरण संख्या 659/2025 दर्ज किया गया है। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4/21ए एवं 4/6 के तहत 24 व्यक्तियों के चालान किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपी

कोटपा अधिनियम में गिरफ्तार आरोपी: योगेन्द्र पुत्र जयनारायण (33 वर्ष), निवासी जोतड़ावाला, सांगानेर सदर — मैनेजर, क्लब हब-40, अनिल कुमार महावर (26 वर्ष), निवासी इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा — वेटर, दीपक बैरवा (25 वर्ष), निवासी रामपुरा रोड, सांगानेर — वेटर

धारा 170 बीएनएसएस 2023 में गिरफ्तार:

विनोद कुमार गुर्जर (27 वर्ष) — बाउंसर, ओम प्रकाश मीणा (28 वर्ष) — बाउंसर, मोहित कुमार शर्मा (31 वर्ष) — बाउंसर

कार्रवाई करने वाली टीम

इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल रामकिशन, कांस्टेबल महेंद्र, अजय, संदीप, शिवराज, ललित, दिनेश एवं चालक कांस्टेबल सतीश शामिल रहे। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जयपुर शहर में अवैध हुक्का बार, डांस बार एवं नाइट क्लबों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर निगम जयपुर सतर्कता शाखा की टीम द्वारा की गई कार्रवाई

-72 हजार 100 रुपये का किया कैरिंग चार्ज वसूल, 10 केन्टर सामान जब्त

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर निगम जयपुर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के निर्देषानुसार एवं पूर्व से प्राप्त शिकायतों पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में मंगलवार को सतर्कता शाखा की द्वारा नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में जेडीए के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए लाल कोठी मण्डी, सहकारी मार्ग, सेन्टल पार्क तथा लोहामण्डी रोड़ माचेड़ा मुरलीपुरा, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, न्यू गेट, लिंक रोड, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, रामगंज, हवामहल बाजार, सिरसी रोड, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, झोटवाड़ा रोड, चांदपोल मेट्रो स्टेशन से अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध 72 हजार 100 रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल कर 10 केन्टर सामान जब्त किया गया।

उपायुक्त सतर्कता ने बताया कि नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार में जेडीए के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही करते हुए लाल कोठी मण्डी, सहकारी मार्ग, सेन्टल पार्क तथा लोहामण्डी रोड़ माचेड़ा मुरलीपुरा, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, न्यू गेट, लिंक रोड, बापू बाजार, चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, रामगंज, हवामहल बाजार, सिरसी रोड, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, झोटवाड़ा रोड, चांदपोल मेट्रो स्टेशन से अस्थाई अतिक्रमण हटवाया गया। उपरोक्त कार्रवाई के दौरान 10 केन्टर सामान जब्त कर गोदाम में भिजवाया गया व अस्थाई अतिक्रमण करने वालों से मौके पर 72 हजार 100 रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया गया तथा दौरे के दौरान कार्यवाही सतर्कता टीम द्वारा मौके पर समझाइष करते हुए मौखिक पाबंद करवाया कि भविष्य में अस्थाई अतिक्रमण समय से हटा ले अन्यथा नगर निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार में अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई:

जोन-9 में 10 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त, शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाए

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए जोन-9 में करीब 10 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही विभिन्न जोनों में सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमण हटाकर मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

आम रास्ता कराया अतिक्रमण मुक्त

जोन-02 के अंतर्गत ग्राम आमेर में दिल्ली बाईपास मुख्य सड़क से जैन मंदिर की ओर जाने वाले गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते पर अज्ञात लोगों द्वारा किए गए कब्जे को हटाया गया। खसरा नंबर 5227, 5239 और 5242 पर लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में बनाई गई कच्ची-पक्की दीवारें, बाउंड्रीवाल, मिट्टी की डोल, तारबंदी और झाड़ियां जेसीबी मशीन की सहायता से हटाकर रास्ता पूरी तरह मुक्त कराया गया।

अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल

जोन-09 के क्षेत्राधिकार में ग्राम भूरथल (जिला जयपुर) में बिना जेडीए की अनुमति एवं बिना भू-रूपांतरण कर करीब 10 बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी की जा रही थी। मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें, प्लॉटों की बाउंड्रीवाल सहित अन्य निर्माण प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिए गए, जिससे अवैध कॉलोनी विकसित करने का प्रयास विफल हो गया।

सड़क सीमा से हटे अस्थायी अतिक्रमण

जोन-01 में नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर पृथ्वीराज मार्ग से वानिकी पथ, सचिवालय क्षेत्र तक दोनों ओर सड़क सीमा से बांस, तंबू, तिरपाल, ठेलों व अन्य सामान हटाए गए। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण में प्रयुक्त सामान जब्त किया गया। इसी तरह जोन-03 में ज्योति नगर मोड़, सहकार मार्ग, लालकोठी, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से अंडरपास तक तथा लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे इंडियाना होटल के सामने और आसपास करीब 100 से अधिक स्थानों पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। नगर निगम के जाप्ते द्वारा 19 ठेले जब्त किए गए।

2025 में अब तक 374 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जेडीए प्रवर्तन प्रकोष्ठ के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक 374 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनियां बसाने के प्रयासों को विफल किया जा चुका है। यह सभी कार्रवाई उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में संबंधित जोनों के राजस्व, तकनीकी स्टाफ एवं प्रवर्तन दस्तों द्वारा की गई। जेडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

कानोता थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई:

25-25 हजार के दो और 10 हजार के एक इनामी खनन माफिया गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस थाना कानोता (जयपुर पूर्व) ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन वांछित खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी 25-25 हजार रुपये के इनामी थे, जबकि एक आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तीनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। आरोपियों पर 15 नवंबर 2025 को अवैध खनन रोकने गई खनिज विभाग की टीम के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा डालने का गंभीर आरोप है। घटना के बाद से ही आरोपी अपने परिवार सहित फरार हो गए थे।

क्या है पूरा मामला

दिनांक 15.11.2025 को परिवादी जैद अली, खनि कार्यदेशक द्वितीय, जयपुर द्वारा थाना कानोता में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम घाटा, अरावली पहाड़ी क्षेत्र (तहसील बस्सी) में अवैध खनन की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मौके पर एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली खनिज चेजा पत्थर का अवैध खनन करते पाए गए। जब टीम ने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की, तभी फैलीराम मीना, नमोनारायण मीना, कृष्ण मीना तथा उनके परिवार के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और खनिज विभाग की टीम के साथ मारपीट कर जब्त वाहनों को छुड़ाने का प्रयास किया। इस संबंध में अभियोग संख्या 896/2025 अंतर्गत, धारा 189(1), 190(2), 121(1), 32, 324(5), 303(2) बीएनएस, धारा 3 पीडीपीपी एक्ट, धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट, तथा आरएमएमसीआर 2017 के नियम 54 व 60 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।

महीनों तक रहे फरार, मोबाइल तक बंद

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव नैन (IPS) के आदेशानुसार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल (RPS) के निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त विनय कुमार डी.एच. (IPS) के निकट सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई। आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए निवास स्थान छोड़ दिया, मोबाइल फोन का उपयोग बंद कर दिया और विभिन्न स्थानों पर छिपते रहे। बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 25-25 हजार रुपये के इनाम घोषित किए गए।

पुलिस टीम ने दिन-रात अथक प्रयास कर 15 दिसंबर 2025 को तीनों आरोपियों को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी

फैलीराम मीना (36) पुत्र जगदीश मीना, निवासी ग्राम घाटा, थाना कानोता

नमोनारायण मीना (46) पुत्र जगदीश मीना, निवासी ग्राम घाटा, थाना कानोता

कृष्ण मीना (24) पुत्र हनुमान मीना, निवासी ग्राम घाटा, थाना कानोता

पहले से भी दर्ज हैं कई संगीन मामले

पुलिस के अनुसार, फैलीराम मीना और नमोनारायण मीना थाना कानोता व थाना बस्सी में दर्ज तीन अन्य गंभीर प्रकरणों में भी लंबे समय से वांछित चल रहे थे, जिनमें अवैध खनन और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से जुड़े मामले शामिल हैं।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

इस कार्रवाई में थानाधिकारी मुनीन्द्र सिंह, उप निरीक्षक रामनिवास, हैड कांस्टेबल दिलीप सिंह सहित कुल 8 पुलिसकर्मियों की टीम शामिल रही। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जयपुर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में मतदाता सूचियों को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित बनाने के उद्देश्य से गत 04 नवंबर से 11 दिसंबर तक गणना चरण संचालित किया गया, जिसके दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक भी आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी की मौजूदगी में आयोजित बैठक में भारतीय जनता पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी.पी.आई.(एम.) एवं आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया गया। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची पर दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) सहित प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र के माध्यम से आवेदक की स्वयं अथवा उनके माता/पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से मैपिंग की जाती है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व जयपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 48 लाख 23 हजार 379 थी, जिन सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। गणना चरण के दौरान 42 लाख 87 हजार 103 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैं। इन सभी मतदाताओं के नाम मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गणना चरण के दौरान दिनांक 04 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर संबंधित बीएलओ द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक आयोजित की गईं। इन बैठकों में बूथ क्षेत्र में अप्राप्त गणना प्रपत्रों की सूची कारण सहित बीएलओ द्वारा बूथ लेवल एजेंट को उपलब्ध कराई गई, ताकि वे इन प्रकरणों का अवलोकन कर अप्राप्ति के कारणों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। इन बैठकों की कार्यवाही विवरण एवं अप्राप्त गणना प्रपत्रों की कारण सहित सूची जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई गई है। मेघराज मीणा ने बताया कि गणना चरण के दौरान कुल 5 लाख 36 हजार 276 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान की वेबसाइट तथा जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में 74 हजार 38 मृत, 3 लाख 39 हजार 490 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 33 हजार 733 अनुपस्थित, 84 हजार 888 मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत तथा 4 हजार 127 अन्य श्रेणी के मतदाता सम्मिलित हैं।

यह सूची संबंधित मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगरीय निकाय कार्यालयों में भी चस्पा की गई है, ताकि यह आमजन एवं नागरिकों के अवलोकन हेतु उपलब्ध रह सके। यह उल्लेखनीय है कि गणना चरण के दौरान एवं उसके पश्चात 28 हजार 578 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 ऑनलाइन तथा 12 हजार 829 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की विहित प्रक्रिया के पश्चात संबंधित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। आमजन वोटर हेल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा संबंधित बीएलओ को फॉर्म-6 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। मेघराज मीणा ने बताया कि वे सभी व्यक्ति, जो दिनांक 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 अथवा 1 अगस्त 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे भी अग्रिम रूप से फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा एवं सुगमता को ध्यान में रखते हुए जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन भी किया गया है। पूर्व में जिले में 4,302 मतदान केन्द्र कार्यरत थे। पुनर्गठन एवं सुव्यवस्थितिकरण के उपरांत 746 नवीन मतदान केन्द्र सृजित किए गए हैं तथा वर्तमान में जिले में कुल 5,048 मतदान केन्द्र हो गए हैं। इस प्रकार जिले में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं रहा है। मेघराज मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचियां फॉर्म-9, 10, 11, 11-ए एवं 11बी में तैयार कर उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएंगी तथा प्रति सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा की जाएंगी।

आवश्यक नम्बर
रॉयल पत्रिका

बिजली फॉल्ट के लिए

टोल फ्री नंबर	18001806507
वॉट्सएप नंबर	9414037085
कस्टमर केयर	2203000
आईवीआरएस	1912

कचरा गाड़ी के लिए

ग्रेटर	2747400
सीवरेज लीकेज	2607500
हेरिटेज	2607500
टोल फ्री नंबर	14420

पुलिस की मदद के लिए

साइबर क्राइम	1930/2360094
कंट्रोल रूम	2388435/36/37/38
ट्रैफिक कंट्रोल रूम	2565630
चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
महिला हेल्पलाइन	1090
मुख्यमंत्री पोर्टल	181

पानी के लिए

जलदाय कार्यालय	2706624
फायर ब्रिगेड	2747400

मेडिकल इमरजेंसी के लिए

एंबुलेंस	102/108
एसएमएस इमरजेंसी	2518333
महिला चिकित्सालय	22610616
जनाना हॉस्पिटल	22378721
SDMH	22574189
SMS ब्लड बैंक	22518222
कल्याण ब्लड बैंक	22721771

घायल पशुओं के लिए

नगर निगम	2747400
बर्ड बाइक	9887345580
हेल्प इन सफरिंग	8107299711
जनमंच ट्रस्ट	7230055800
पशु चिकित्सालय	2747400

पाली जिला वक्फ कमेटी में युवा प्रतिनिधित्व को मिला बल, निजाम खान सोढा सदस्य नियुक्त

मोहम्मद यासीन

पाली। (रॉयल पत्रिका) । पाली जिला वक्फ कमेटी ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए निजाम खान सोढा को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर समाज के विभिन्न वर्गों में हर्ष का माहौल है और लोगों ने उन्हें बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ दी हैं। पाली जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष सलीम एमडी ने बताया कि कमेटी में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, सुव्यवस्थित प्रबंधन और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए युवा शक्ति की सक्रिय भूमिका बेहद आवश्यक है। युवाओं के जुड़ने से वक्फ से संबंधित कार्यों की समझ बढ़ेगी और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। नवनियुक्त सदस्य निजाम खान सोढा ने कमेटी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और समग्र विकास उनकी प्राथमिकता रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। निजाम खान सोढा की नियुक्ति को सकारात्मक पहल बताते हुए क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई है कि उनके जुड़ने से पाली जिला वक्फ कमेटी के कार्यों को नई दिशा मिलेगी और वक्फ संपत्तियों के विकास से जुड़े प्रयास और मजबूत होंगे।

क वर्ग व्यापार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने किया स्वागत

बारां (रॉयल पत्रिका)। हाल ही में संपन्न हुए कृषि उपज मंडी क वर्ग व्यापार संघ के चुनाव में निर्वाचित हुए अध्यक्ष मनीष लश्करी का मंगलवार को दी पब्लिक कैरियर ट्रक ऑनर्स संस्थान बारां के कार्यालय पर ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों ने स्वागत सत्कार किया। ट्रक ऑनर्स संस्थान के जनरल सेकेट्री मन्नू पठान ने बताया कि संस्थान के कार्यालय पर नवनिर्वाचित मंडी अध्यक्ष मनीष लश्करी का संस्थान के अध्यक्ष श्याम कुमार बंसल, उपाध्यक्ष अमित कुमार मेहता, जनरल सेकेट्री मन्नू पठान, कोषाध्यक्ष पवन गोस्वामी, बोर्ड इंचार्ज सत्यनारायण गुप्ता ने माला पहनाकर साफाबंदी कर मुंह मीठा करवाकर ओर स्मृति चिन्ह भेंट कर ऐतिहासिक स्वागत किया। स्वागत सत्कार कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष भीमसेन अदलक्खा, ध्रुव कुमार यादव, खुर्शीद आलम, रईस अहमद, अकील भाई, मकसूद अहमद, पप्पू भाई, रियाज अहमद सहित संस्थान के पदाधिकारी ओर स्टॉफ मौजूद रहे। इस मौके पर मंडी समिति ओर ट्रक यूनियन में आपसी सहयोग बनाए रखने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में संस्थान के जनरल सेकेट्री मन्नू पठान से सभी अतिथियों ओर यूनियन के पदाधिकारियों का आभार प्रकट किया।

उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर के बालकों ने किया एक्सपोजर विजिट

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। सवाई माधोपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर के बालकों ने भारत मानक ब्यूरो के तत्वाधान में कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर का एक्सपोजर विजिट किया। शारीरिक शिक्षक नफीस अहमद ने बताया कि विजिट में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर ने बालकों को कृषि के क्षेत्र में कैरियर और कृषि मानकों के बारे में विस्तार से समझाया और केंद्र का भ्रमण करवा कर कृषि की जानकारियां प्रदान की गई इस अवसर पर BIS प्रभारी अजहरुद्दीन खान,मनीषा गुर्जर आदि उपस्थित रहे।

ओवरलोड बसों की बदहाल स्तिथि का जिम्मेदार कौन? नियमों का पालन नहीं

-ओवरलोड बसों में सफर कर रहे लोगों की जान को खतरा

हनीस खान कुतकपुर

हिंडौन सिटी (रॉयल पत्रिका)। आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे की, जो अक्सर खबरों में रहता है - बसों में ओवरलोडिंग। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यात्रियों की जान से जुड़ा सवाल है। यह नजारा फैली का पूरा टोल टैक्स व कटकड़ स्टेण्ड का है ,यानि कि करौली हिंडौन सड़क मार्ग व गंगापुर हिंडौन सड़क मार्ग का जहाँ हर रोज़ देखने को मिलता है कि कैसे अपनी क्षमता से कहीं ज़्यादा यात्रियों को बसों में ठूंस-ठूंस कर भरा जा रहा है। बस की छतो पर बेखौफ बैठा कर यात्रियों को ले जाते हुए जिला पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं लेकिन प्रशासन से बैंखौफ होकर धड़ल्ले से चल रही है ओवरलोडिंग बस सवारियों को छतो पर बिठाकर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के आंखे के आगे से सड़कों पर लगातार दौड़ रही है ओवरलोडिंग बसे परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार, 32-सीटर बस में लगभग 30 यात्री होने चाहिए, लेकिन अक्सर यहाँ 100 से ज्यादा लोग भरे जाते हैं। यह सिर्फ एक बस की कहानी नहीं, यह पूरे क्षेत्र की समस्या है, जहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की मिलीभगत का नतीजा आम लोगो कों ना चुकाना पड जाये यह स्थिति बताती है कि यात्रियों की जान कितनी खतरे में है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पर ठोस कार्रवाई करता है। यह घटनाएँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अपनी सुविधाओं के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, या प्रशासन अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। यह एक गंभीर सवाल है, जिस पर सरकार और संबंधित विभागों को ध्यान देना चाहिए। ओवरलोड बसों की बदहाल स्तिथि जिम्मेदार कौन।

कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

पाली (रॉयल पत्रिका)। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशनुसार मोदी,शाह सरकार द्वारा ED व अन्य संवैधानिक संस्थानों के दुरूपयोग के विरोध में तथा माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी पर लगाए गए झूठे मुकदमों को ख़ारिज करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाई गई है। यह स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ED व अन्य संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आदेशानुसार पाली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध एवं विशाल धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा ED सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या एवं विपक्षी दलों की आवाज़ दबाने की साज़िश के विरोध में जिला स्तर पर आज विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। लोकतंत्र विरोधी रवैये के खिलाफ तानाशाही के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की तथा मनरेगा का नाम बदलने की साजिश महात्मा गांधी जी के नाम से भाजपा की चिढ़ जगजाहिर है। करोड़ों ग्रामीणों की जीवनरेखा 'मनरेगा' का नाम बदलने का प्रयास पूरी तरह अनुचित है। यह केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि गरीबों के हक पर प्रहार है।

मनरेगा बचेगा मजदूर बचेगा-

महात्मा गांधी के नाम का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता रफीक चौहान ने बताया कि इस मौके पर जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाडा, लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने भाजपा की केंद्र सरकार गलत नीतियों को लागू कर प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है, पाली विधायक भीमराज भाटी ने कहा राजस्थान की पर्ची सरकार गरीबों को 100 दिन के रोजगार से वचिंत कर गुमराह कर रही है। पुर्व जिलाध्यक्ष अजीज दर्द, पीसीसी सदस्य शोभा सोलंकी, पाली शहर ब्लॉक अध्यक्ष हकीम भाई, रोहट ब्लॉक अध्यक्ष पीराराम पटेल, बाली ब्लॉक अध्यक्ष यशपाल सिंह राजपुरोहित, सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेहपाल सिंह पावा, पुर्व ब्लॉक अध्यक्ष मेहबूब टी, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव नीलम बिरला, अरुण जोशी, सेवादल जिलाध्यक्ष प्रकाश चौधरी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गोवर्धन देवासी, भंवर राव, महिला जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला, पुर्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण कोठारी, पुर्व ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी सिंह राजपुरोहित, राजीव गांधी पंचायत राज के जिलाध्यक्ष मदनसिंह जागरवाल, रतन उदेश, सज्जन बी राज, राजेन्द्र सिंह कूम्पावत, संतोख सिंह बाजवा, आनंद सोलंकी, सुभाष मेवाड़ा, प्रकाश सांखला, जिला प्रवक्ता रफीक चौहान, जीवराज चौहान, मांगुसिंह दूदावत, यशपाल सिंह कूम्पावत, मंगलाराम भिण्डर, बाबूलाल दहिया, मण्डल अध्यक्ष अशोक गौड, चेलाराम रारबडा, रघुनाथ सिंह मण्डली, राजेंद्र मेघवाल, राजू बंजारा, प्रकाश सोनी, रमेश चावला, एस सी जिलाध्यक्ष सुनील बैरवा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष जावेद सिरोहा, ओबीसी जिलाध्यक्ष गोविंद बंजारा, जयसिंह सुकरलाई, कृष्णा सांसी, कालुराम विश्नोई, हितेश सिरोया, माणक गर्ग, रमेश चौधरी, दिनेश पंवार, वजीर खां, हैप्पी मेवाडा, साबीर अशरफी, सत्य प्रकाश पटेल, भेराराम गुर्जर, तालिब चुडीगर, ताराचंद चन्दनानी, सहित सैकड़ों कांग्रेसजनो ने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध जताया।

सीएलजी बैठक में सुरक्षा पर मंथन, हस्तेड़ा में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

चौमूं (रॉयल पत्रिका)। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी विनोद सांखला ने हस्तेड़ा पुलिस चौकी परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में बढ़ती चोरियों की रोकथाम को लेकर नागरिकों से सतर्क रहने और पुलिस को सहयोग देने की अपील की गई। थाना प्रभारी सांखला ने कहा कि अपराध नियंत्रण में जनभागीदारी अहम है। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने, रात्रि गश्त में सहयोग और आपसी समन्वय से ही अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस के संकल्प को दोहराते हुए कहा— "अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास" हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर सीएलजी सदस्य मालीराम यादव गंगासागर सहित ग्रामीण सदस्य गण उपस्थित रहे। बैठक में हस्तेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष मालीराम मिश्रा ने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की घोषणा की गई, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी मजबूत होगी और अपराधियों पर लगाम लगेगी। सीएलजी सदस्यों ने भी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के सुझाव दिए और पुलिस के साथ मिलकर कार्य करने का भरोसा जताया। पुलिस चौकी प्रभारी जगदीश सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि अपराधी गतिविधियों में निफ्ट व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने की अपील की।

इंसानियत एकता सेवा समिति का रात्रिकालीन कम्बल वितरण अभियान का शुभारम्भ

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर देर शाम को भाईजी चौक स्थित राणाजी के नोहरे में इंसानियत एकता सेवा समिति द्वारा समिति व्यवस्थापक इंजीनियर जाफर खान के नेतृत्व में रात्रिकालीन कम्बल वितरण अभियान का शुभारम्भ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति वरिष्ठ उपाध्यक्ष महमूद अली राणा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच डॉ. अयूब खान सेहला थे। इस अवसर पर समिति संस्थापक करामत खान ने बताया कि अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कम्बल वितरित कर उन्हें सर्दी से बचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत शीतकालीन सत्र में चूरू सहित पूरे शेखावाटी क्षेत्र में फुटपाथ व सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले और कच्ची बस्तियों में रहने वाले असहाय व ज़रूरतमंद लोगों को कम्बल व ऊनी वस्त्र वितरित किए जाएंगे। समिति कोषाध्यक्ष रियाज अहमद खान ने बताया कि अभियान के तहत 400 कम्बल वितरित की जाएंगी। इस दौरान समिति मीडिया प्रभारी मोहम्मद अली पठान, निदेशक सदस्य अयूब खान, सहायक सचिव डॉ. शाहरुख खान, संरक्षक सदस्य आमीन खान, इमरान बी खान, अजीज खान, डॉ. इदरीस खान गौड़, डॉ. अखतर खान, नौशाद खान, हाजी जोरावर खान, आवेश कुरैशी, सुलेमान मणियार, मो. अली खान, सलीम खान, सलमान खान, असलम खान, गफार खान, मोहम्मद राशिद, एडवोकेट इब्राहीम गौरी, गुलाम हुसैन गौरी, मो. रफीक राजगढ़िया, दानिश पठान, मौलवी अब्दुल्लाह खान, प्र.अ. अशफाक खान, महबूब खान, साबिर खान, रहमान खान, परवेज खान, बिलाल खान, यूसुफ खान, साजिद खान, हमीद खान, अलादीन खान, सोयल खान, जाकिर अली खान, अबरार खान, शमशाद खान, खानू खान, आसिफ शैख, आसिफ लुहार आदि मौजूद रहे। समिति उपाध्यक्ष वसीम अली ने सभी का आभार जताया। इंसानियत एकता सेवा समिति का रात्रिकालीन कम्बल वितरण अभियान का शुभारम्भ ।

नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ आयोजित, भामाशाह कैलाश पारीक का किया सम्मान

चौमू (रॉयल पत्रिका)। महर्षि पराशर पारीक सेवा समिति चौमू के तत्वावधान में पारीक समाज की ओर से ग्राम डोला का बास निवासी भामाशाह कैलाश पारीक का नागरिक अभिनंदन एवं स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में ग्राम डोला का बास के पुरोहितों की ढाणी स्थित ओंकारेश्वर धाम में हाल ही में संपन्न तीन दिवसीय नानी बाई रो मायरो कथा के सफल आयोजन पर कथा संयोजक भामाशाह कैलाश पारीक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज की ओर से उन्हें अभिनंदन पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माल्यार्पण व साफा ओढ़ाकर सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में भामाशाह कैलाश पारीक ने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में धार्मिक चेतना का संचार होता है तथा सर्व समाज में आपसी सद्भाव और संस्कारों को बल मिलता है। समिति अध्यक्ष रामअवतार पारीक ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों से समाज में एकता, संस्कार और सेवा भावना को मजबूती मिलती है। उन्होंने भामाशाह कैलाश पारीक के सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में भी समाजहित में निरंतर कार्य करते रहने की शुभकामनाएं दीं। समारोह के दौरान महर्षि पराशर पारीक सेवा समिति की ओर से आगामी पारीक समाज अखिल सामूहिक विवाह सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। समिति के अनुसार यह सम्मेलन 23 जनवरी को आदर्श विद्या मंदिर, चौमू में आयोजित किया जाएगा। समाजबंधुओं से अधिक से अधिक सहभागिता का आह्वान किया गया। इस अवसर पर समिति संयोजक भगवान सहाय पारीक, कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण पारीक, उपाध्यक्ष मोहनलाल डाबड़ी, व्यवस्थापक सोहन पारीक सहित अनेक पारीक समाज के लोग उपस्थित थे।

मृत्यु भोज का बहिष्कार कर शिक्षा के लिए भूमिदान

-समाज के सामने रखी अनुकरणीय मिसाल

चौमू (रॉयल पत्रिका)। ग्राम पंचायत डोला का बास स्थित शहीद रामकरण मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक लालाराम मीणा ने अपनी माता स्वर्गीय बनारसी देवी एवं पिता स्वर्गीय रुडमल मीणा की स्मृति में विद्यालय को 150 वर्गगज भूमि तथा 21 हजार रुपये की नगद राशि भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने अपनी माता के देहांत पर मृत्यु भोज का पूर्ण बहिष्कार कर सामाजिक सुधार की दिशा में सराहनीय पहल की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेलकूद निदेशालय बीकानेर के उपनिदेशक रामसिंह मीणा ने कहा कि इस तरह के कार्य समाज को नई दिशा देने वाले होते हैं। उन्होंने भामाशाह परिवार के प्रति आभार जताते हुए इसे शिक्षा और सामाजिक चेतना के लिए प्रेरक कदम बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा मीणा ने की। उन्होंने कहा कि भूमि दान विद्यालय के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशिष्ट अतिथियों में सरपंच सुल्तानराम बुनकर, पीईईओ प्रकाश मानावत, पूर्व उपप्रधानाचार्य मुकेश हाटवाल, मालीराम मीणा, सी.एम. मीणा, जीवतराम फौजी, डॉ. श्योजीराम यादव, गोपाल मीणा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक संजय कुमार जैन एवं अध्यापक कमलकांत मीणा ने किया।

ताइक्वांडो टूर्नामेंट में मार्शल आर्ट अकैडमी चुरु ने 11 गोल्ड मेडल दो ब्रान्ज मेडल हासिल किया

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर आयोजित डिस्ट्रिक्ट ताइक्कांडो टूर्नामेंट में ब्लैक नाइट्स मार्शल आर्ट्स अकादमी चूरू के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए 11 गोल्ड मेडल एवं 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। जिसमे कोच चरण सिंह उर्फ योगी जी व कोच नरपत जी दुधवा खारा ने बताया कि मानवेंद्रपाल सिंह ने गोल्ड,प्रवीण सिंह ने गोल्ड, शौर्य कालेर ने गोल्ड, उत्तम ने गोल्ड, हर्षवर्धन ने गोल्ड, जयवर्धन ने गोल्ड, यशवर्धन ने गोल्ड, कृष्ण ने गोल्ड, बिलाल ने गोल्ड, गर्वित ने ब्रॉन्ज, दीपांशु ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। लड़कियों में दिव्यांशी ने गोल्ड, शिवानी ने गोल्ड जीता एवं सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया व गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी राज्यस्तर ताइक्कांडो प्रतियोगिता में भाग लेंगे।

मेडिकल कॉलेज चूरू में सुपर स्पेशलिस्ट की कमी: आठ साल बाद भी मरीजों को करना पड़ रहा है रेफर

-प्रिंसिपल डॉ. एमएम पुकार ने भेजे सुविधाओं के प्रस्ताव

मोहम्मद अली पठान

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना को आठ वर्ष हो चुके हैं, जहां प्रतिवर्ष 150 डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। इसके बावजूद, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी के कारण डीबी अस्पताल से गंभीर मरीजों को आज भी जयपुर और बीकानेर रेफर करना पड़ रहा है। सरकार ने 400 बेड का आधुनिक अस्पताल भवन तैयार कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति न होने से आमजन को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति कॉलेज की स्थापना के मूल उद्देश्य पर सवाल खड़े करती है। मेडिकल सुविधाओं के विस्तार और रोगियों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. एम.एम. पुकार ने राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण मांगों का प्रस्ताव भेजा है। इन मांगों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और आधारभूत ढांचे के विकास की मांगें प्रमुख हैं। प्रिंसिपल डॉ. पुकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की मांग की गई है। इनमें 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन, टेस्ला एमआरआई मशीन, कैथ लैब, 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और भरतिया अस्पताल के 6 वार्डों का नवीनीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में 2 ऑटोमेटेड फूड कोर्ट, 4 बड़े वेटिंग हॉल, 100 कमरों का गेस्ट हाउस, एक आधुनिक लाइब्रेरी, रिक्रिएशन कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट ग्राउंड और 1500 सीट क्षमता का ऑडिटोरियम जैसी सुविधाओं की भी मांग की गई है। छात्रों के लिए एक स्किल लैब, तीन स्मार्ट क्लासरूम, 600 यूजी छात्रों के लिए हॉस्टल और 72 पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल की भी आवश्यकता बताई गई है। चिकित्सा सुविधाओं को सुदृद्ध करने के लिए मॉडर्न ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पांच

मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की भी मांग की गई है, ताकि गंभीर मरीजों को तत्काल और उन्नत उपचार मिल सकें। मेडिकल कॉलेज में नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शेष कार्य पूर्ण होते ही अस्पताल की छह प्रमुख यूनिटें मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, रेडियोलॉजी और एनेस्थीसिया नई बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दी जाएंगी।पुराने अस्पताल भवन में स्किन, आई, मनोरोग, पीडियाट्रिक और प्रसूति विभाग संचालित होते रहेंगे, जिससे मरीजों को विभिन्न विशिष्टताओं में उपचार मिलता रहेगा। डॉ. पुकार ने यह भी बताया कि मेडिकल कॉलेज भवन में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी,फार्माकोलॉजी,माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे आठ विभाग पहले से ही संचालित हैं। चार सुपर स्पेशलिस्ट को मिली स्वीकृति राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग की ओर से चार सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए 10.58 करोड़ रुपए का बजट सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जा चुका हैं। लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर ने जॉइनिंग नहीं की है। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये चारों सुपर स्पेशलिस्ट चूरू में सेवाएं देना शुरू करेंगे। उसी दिन से मरीजों का रेफर अनुपात लगभग शून्य हो जाएगा। एनएमसी की आपत्तियों का किया गया निस्तारण वर्ष 2023 में एनएमसी द्वारा जारी थो-कॉज नोटिस में 10 प्रमुख कमियां बताई गई थीं। जिनके कारण कॉलेज पर एक करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। इसमें ब्लड बैंक लाइसेंस (2022 से एक्सपायर) का 2025 में नवीनीकरण करवाया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट (2023 से एक्सपायर) का 2025 में नवीनीकरण करवाया। हिस्टोपैथोलॉजी लैब शुरू करवायी। कम बेड ऑक्यूपेंसी की समस्या, जिसे नए अस्पताल के संचालन से पूरा किया जाएगा। वर्ष 2025 में कॉलेज की एथिकल कमेटी की स्वीकृति आदि कमियों का समाधान कर लिया गया हैं।

आर्ट गैलरी में सजी दो साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, जिला कलक्टर ने किया शुभारंभ

-विकास प्रदर्शनी में विभागों ने लगाए स्टॉल, गरड़दा परियोजना का मॉडल बना आकर्षण का केंद्र
-जिला विकास पुस्तिका का भी हुआ विमोचन

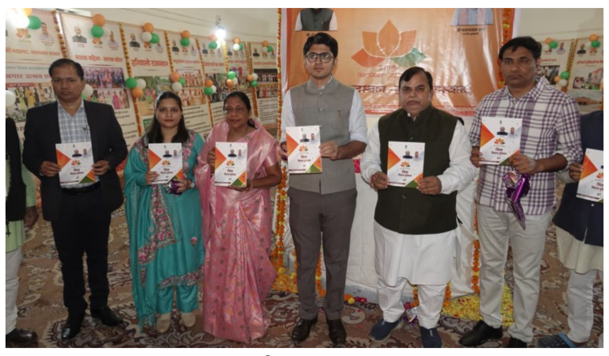

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार के कार्यकाल के सफल दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से आर्ट गैलरी में आयोजित की जा रही तीन दिवसीय 'जिला विकास प्रदर्शनी' का जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जिले में बीते दो वर्षों में हुए बदलाव और विकास कार्यों की सराहना करते हुए इसे आमजन के लिए प्रेरणादायक बताया। प्रदर्शनी के उद्‌घाटन समारोह में नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, अतिरिक्त जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी अनुप्रिया,राजकुमार श्रृंगी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

फ्लेक्स पैनल्स पर उकेरी गई विकास की कहानी-

आर्ट गैलरी में प्रवेश करते ही फ्लेक्स पैनल बोर्ड्स के माध्यम से राज्य और बूंदी जिले की प्रगति की कहानी बयां की गई है। प्रदर्शनी में पिछले दो वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों को बेहद आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। जिला कलक्टर ने एक-एक पैनल का बारीकी से अवलोकन किया और प्रदर्शित चित्रों के माध्यम से दर्शायी गई विकास यात्रा की प्रशंसा की।

विभागीय स्टॉल्स पर दिखी प्रगति, गरड़दा मॉडल को मिली सराहना-

प्रदर्शनी परिसर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अपनी उपलब्धियों को दर्शाने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें जयपुर विद्‌त वितरण निगम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद, शिक्षा, महिला अधिकारिता, स्वच्छ भारत मिशन, जिला मत्स्य विकास परियोजना और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपने स्टॉल के माध्यम से विभागीय प्रगति का प्रदर्शन किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किया गया 'गरड़दा पेयजल एवं सिंचाई परियोजना' का मॉडल प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण बना रहा। आमजन और अतिथियों ने इस मॉडल को खूब सराहा। कलक्टर अक्षय गोदारा ने प्रत्येक स्टॉल पर जाकर वहां मौजूद अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली।

'जिला विकास पुस्तिका' का विमोचन-

इस अवसर पर जिला कलक्टर ने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, बूंदी द्वारा प्रकाशित 'जिला विकास पुस्तिका' का विमोचन भी किया। पुस्तिका में बीते दो सालों में बूंदी जिले में हुए विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समावेश किया गया है, ताकि आमजन एक ही जगह पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकें। साथ ही, विभाग की ओर से प्रचार साहित्य का वितरण भी किया गया।

जल संसाधन मंत्री ने अजमेर में जिला विकास प्रदर्शनी का शुभारम्भ एवं जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन

-राज्य सरकार द्वारा दो वर्ष में किए गए ऐतिहासिक कार्यों एवं उपलब्धियों की विस्तार से दी जानकारी

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने राज्य सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 2 साल नव उत्थान-नई पहचान, बढ़ता राजस्थान-हमारा राजस्थान थीम पर आधारित तीन दिवसीय जिला विकास प्रदर्शनी का मंगलवार को सूचना केंद्र की आर्ट गैलरी में फीता काटकर शुभारम्भ किया एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यों पर आधारित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। जिला कलक्टर लोक बन्धु ने जिला विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। जल संसाधन मंत्री ने राज्य सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अतिथियों ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विगत दो वर्ष में विभिन्न विभागों द्वारा फ्लैगशिप तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों एवं नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। रावत ने राज्य सरकार के दो वर्ष के सफलतम कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार राजस्थान के चहुंमुखी विकास के संकल्प को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्ष में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किए गए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 एवं 2025-26 में प्रदेश को विकास की ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। इनमें अधिकांश घोषणाएं क्रियान्वित की जा चुकी है। साथ ही प्रगतिरत बजट घोषणाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए उन्हें पूर्ण करने की दिशा में निरन्तर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान इनवेस्टमेंट समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इसमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा विद्‌त उत्पादन में आत्मनिर्भरता अर्जित की गई। इसमें 5 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित की गई। युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए। इसमें 92 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। एक लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अजमेर को दोनों बजटों में विकास की ऐतिहासिक सौगातें दी हैं। इनमें पेयजल समस्या के निदान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी के माध्यम से मोर सागर बांध की सौगात दी। इस बांध का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इसके निर्माण में 4 हजार 700 करोड़ रुपए से अधिक राशि का व्यय होगा। इसके पश्चात बिसलपुर बांध के माध्यम से इसे भरा जाएगा। आगामी समय में बांध द्वारा जिले को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई है। इसी प्रकार जिले में विभिन्न विकास कार्य निरन्तर चल रहे है। राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को देने के लिए विकास रथ संचालित किए है।

भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किए जाने पर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका एवं विरोध प्रदर्शन किया

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला मुख्यालय पर प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ लगातार की जा रही ईडी और सीबीआई की कार्यवाही के विरोध में चूरू जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष व सुजानगढ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूरू जिला कलेक्ट्रेट आपणी योजना के आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल ने कहा कि भाजपा के इशारे पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ की जा रही जांच एजेंसियों की कार्यवाही बदले की भावना को दर्शाती है। यह सुशासन का नही, बल्कि कुशासन का संकेत है। उन्होने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने घुटने नही टेके, तो भाजपा से भी डरने वाली नही है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लडाई जारी रखेगे। मनोज मेघवाल ने कहा कि सत्य कभी प्राजीत नही होता आखिर सच्चाई की जीत हुई। न्यायालय ने ईडी द्वारा की कार्यवाही पर रोक लगाकर सच्चाई एक बार फिर साबित हुई है। इस दौरान रियाजत खान, असलम खोखर, किशोर धान्धू, मुस्ताक खान, इदरिश गौरी, संजय कस्वा, जमील चौहान, आदूराम न्यौल, आशाराम सैनी, आसीफ खान, सुरेश कल्ला, सुनिता कपुरिया, विकाश मील, मोसीन खान, रामनिवास साहरण, विधाधर मेघवाल, प्रदीप तोदी, बजरंगलाल सैन, महेन्द्र डुकिया, विजयपाल चाहर, कल्याण सिंह शेखावत, राजकुमार इंदोरिया, रामचन्द्र गोदारा, रमेश राव, नारायण बालाण, अरविन्द चाकलान, शेर खां मलखाण संजय भाटी, आरिफ पिथिसर, विधाधर बेनीवाल, अमीत मारोठिया, अजीज खान, विमल शर्मा, आसीफ निर्बाण, तौफिक खान पार्षद, प्यारेलाल दानोदिया, सद्दाम हुसैन, सोयल डीके, शिवकुमार शर्मा, अबरार खान, समीउल्लाह गौरी, अख्तर खान, रामप्रताप कांटीवाल, लोकेश सैनी, सोहनलाल मेघवाल, रतनलाल जांगिड, अब्बास काजी, बजरंग बजाड, किशनाराम बाबल, आबिद मोयल, शाहरूख खान, अज्जू लुहार, अल्ताफ लीलगर, ज्योति सिंह, बालीबाई, प्रमिला भाकर, भादरराम, अब्दुला कुरेशी, सहित सैकडो कांग्रेस कार्यकर्ता मौजुद रहें।

जिले में मतदाता सूची का प्रारुप प्रकाशन, 65703 के फॉर्म अप्राप्त, 39752 शिफ्ट हुए

-सुविधा: 1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथों का पुनर्गठन, 143 नए मतदान केंद्र बनाए; 15 जनवरी तक जुड़वा सकेंगे नाम
-जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्येक्षता में आयोजित हुई बैठक, राजनीतिक दलों को सौंपी सूची, मांगे सुझाव

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर बदल गई है। पुनरीक्षण से पहले जिले में 8,97,906 मतदाता थे। बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र बांटे, जिनमें से 8,32,203 फॉर्म भरे हुए वापस मिले। लेकिन 65,703 गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे। अप्राप्त गणना प्रपत्रों में स्थायी रूप से स्थानांतरित 39,752, मृत 14151, अनुपस्थित 8241, एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 3311 तथा अन्य कारण 248 मिले। प्रशासन ने पारदर्शिता बरतते हुए इनकी सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट (WWW.ELECTION.RAJASTHAN.GOV.IN) एवं जिले की वेबसाइट (HTTPS://BUNDI.RAJASTHAN.GOV.IN) और मतदान केंद्रों, ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं नगरीय निकाय कार्यालयों पर चस्पा कर दी है, ताकि आमजन देख सकें। मतदाताओं की सुविधा हेतु 1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथों का पुनर्गठन किया गया हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में पहले 895 मतदान केंद्र थे, जिनका पुनर्गठन कर 143 नए केंद्र सृजित किए गए हैं। अब 1038 मतदान केंद्र हो गए हैं। अब 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केन्द्र शेष नहीं है।

राजनीतिक दलों को सौंपी सूची, मांगे सुझाव-

आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा की अध्य क्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए/प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें भारतीय जनता पार्टी से जिलाध्यपक्ष रामेश्वर मीणा, अमित निम्बार्क, इंडियन नेशनल कॉग्रेस पार्टी से जिलाध्य क्ष महावीर मीना, मनीष गौत्तम, महावीर मीना, आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष अरविन्द सिंह, कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट) पार्टी से बाबूलाल बैरवां उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा इन्हें मतदाता सूची की हार्ड व सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई। साथ ही अप्राप्त फॉर्मों की सूची भी दी गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या हटवाने के लिए दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। जो युवा 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल के हो रहे हैं, वे अभी से फॉर्म-6 भरकर अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 'वोटर हेल्पलाइन ऐप', 'वोटर सर्विस पोर्टल' या बीएलओ के जरिए आवेदन किया जा सकेगा।

वन राज्य मंत्री ने अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारम्भ

-विकास रथ का किया स्वागत, आमजन को प्रचार सामग्री की वितरित

अलवर (रॉयल पत्रिका)। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने रविवार को अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 के तहत आयोजित अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का राजऋषि महाविद्यालय के खेल मैदान में बैटिंग कर शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने प्रतियोगिता की ट्रॉफी का विमोचन भी किया। वन राज्यमंत्री श्री शर्मा ने मैच देखकर खिलाडियों की हौसला-अफजाई करते हुए टीम भावना के साथ खिलाडियों को खेल में अच्छा प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव द्वारा खेल प्रतिभाओं को निखारने एवं उनको आगे बढाने के लिए अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से खेल का बेहतर प्लेटफार्म उपलब्ध कराने पर उनको साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के माध्यम से ना केवल खिलाडियों को खेल मंच प्रदान किया जा रहा है, बल्कि खिलाडियों को सांई के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठों विधानसभाओं में कम्युनिटी खेलों का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में खिलाडी बढचढकर उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अलवर शहर विधानसभा कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता की ट्रॉफी का विमोचन भी किया। सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान ने कहा कि अलवर के खिलाडियों की खेल प्रतिभा को निखार कर उन्हें खेल का बेहतर मंच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव ने अलवर सांसद खेल उत्सव की शुरूआत की है।

विकास रथ का किया स्वागत, आमजन को प्रचार सामग्री की वितरित—

वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आए विकास रथ का राजऋषि महाविद्यालय खेल मैदान में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने दो वर्षों में प्रदेश के चहुंमुखी विकास एवं आमजन के सर्वांगीण कल्याण की भावना से ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपने दोनों बजटों में अलवर को विकास की महत्वपूर्ण सौगातें दी गई, जिससे अलवर के विकास को गति मिली है। उन्होंने आमजन से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ उठाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने विकास रथ में लगी एलईडी स्क्रीन पर सरकार की योजनाओं के वीडियो संदेश को देखा तथा आमजन को प्रचार सामग्री वितरित की।

कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन नेशनल हेराल्ड केस: न्यायालय के फैसले के बाद

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। नेशनल हेराल्ड मामले में माननीय न्यायालय द्वारा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर आए हालिया घटनाक्रम के बाद आज जिला कांग्रेस कमेटी सवाई माधोपुर में भारी रोष देखने को मिला। कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमन ने जानकारी देते हुए बताया कि बामनवास विधायक एवं जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि माननीय न्यायालय के रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ED की कार्रवाई पूरी तरह से फर्जी, राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सत्य की जीत हुई है। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष नगर अध्यक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने एकजुट होकर केंद्र की नीतियों का विरोध किया।

यूरिया की निरंतर आपूर्ति जारी, कालाबाजारी पर सख्त निगरानी

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिले में रबी फसल 2025 के अंतर्गत गेहूं की बुवाई एक साथ होने के कारण यूरिया उर्वरक की मांग में वृद्धि हुई है। माह अक्टूबर में जिलेभर में हुई अच्छी वर्षा के चलते किसानों द्वारा व्यापक स्तर पर गेहूं की बुवाई की गई है। गत वर्ष गेहूं का क्षेत्रफल 1,40,150 हेक्टेयर था, जबकि रबी 2025 में अब तक 1,55,110 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बुवाई हो चुकी है, जिससे यूरिया की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ी है। रबी 2025 में जिले की कुल अनुमानित मांग 55,500 मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध अब तक लगभग 46,000 मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति हो चुकी है। जिले में यूरिया की आपूर्ति निरंतर जारी है। हाल ही में इफको की एक रैक प्राप्त हो चुकी है तथा इसी सप्ताह 1–2 अतिरिक्त रैक और प्राप्त होने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकता अनुसार ही उर्वरक का क्रय करें तथा तरल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग करें, जिससे पौधों को नाइट्रोजन की सटीक मात्रा प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि यूरिया में नाइट्रोजन की उपयोगिता लगभग 30 प्रतिशत ही होती है, शेष मात्रा भूमि या वायुमंडल में नष्ट हो जाती है। जिले में यूरिया की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। उर्वरक विक्रेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हुए किसानों को उर्वरक का विक्रय करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुण नियंत्रण अभियान के अंतर्गत निर्धारित 366 नमूनों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2,508 उर्वरक नमूने लिए जा चुके हैं। जिले में 583 उर्वरक विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया, 72 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तथा 16 उर्वरक अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रकरणों में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रयोगशाला द्वारा अमानक घोषित उर्वरकों के मामलों में संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध माननीय न्यायालयों में 21 इस्तगासे भी दायर किए गए हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को तीन दिन में दी 6 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

अजमेर (रॉयल पत्रिका)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विगत तीन दिनों में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। इन कार्यों के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे आमजन को बेहतर आवागमन, सुचारू जल निकासी, पेयजल, सुरक्षा एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सकेगा। इसी क्रम में रविवार को देवनानी द्वारा नागफणी क्षेत्र में बद्री विशाल मंदिर के सामने आयोजित कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वार्ड 5 में बद्री विशाल मंदिर से शास्त्री कॉलोनी तक नाले के निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस पर लगभग एक करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये की लागत आएगी। यह नाला वर्षों से चली आ रही जलभराव की समस्या एवं कच्चे नाले के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न परेशानियों के स्थायी समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस नाले का निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराया जाएगा। नाले के निर्माण से नागफणी क्षेत्र के निवासियों को जलभराव से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अजमेर उत्तर क्षेत्र में अब तक लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत से 15 नालों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके सकारात्मक परिणामस्वरूप क्षेत्र धीरे-धीरे जलभराव की समस्या से मुक्त हो रहा है। इसके पश्चात देवनानी ने बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अंतर्गत वार्ड 5 स्थित भागचंद सोनी नगर में स्वीकृत विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन सड़कों का निर्माण लगभग 16 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती हैं। मजबूत सड़कें आवागमन को सुगम बनाने के साथ व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी गति प्रदान करती हैं।

नि:शुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का हुआ शुभारंभ

बूंदी (रॉयल पत्रिका)। जिले में आमजन को जटिल गुदरोगों से मुक्ति दिलाने के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क आवासीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ किसान भवन, पुरानी धानमंडी में मंगलवार को हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा रहे। अध्यक्षता पूर्व विधायक ओमप्रकाश डिंगल ने की। विशिष्ट अतिथि नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल एवं पूर्व विधायक अशोक डोगरा रहे। अतिथियों ने धन्वंतरी भगवान की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान रामेश्वर मीणा ने कहा की आमजन जीवन में आयुर्वेद अपना कर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं साथ ही आयुर्वेद का शरीर के लिए कोई नुकसान भी नहीं है। आयुर्वेद अपनाने से बीमारी जड़ से समाप्त होती है। आमजन से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और आयुर्वेद चिकित्सा की ओर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क शिविर आमजन के लिए अच्छास अवसर है, जिसका लाभ उठाकर वे कष्टसाध्य रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन में प्रतिदिन योग को अपनाये। सहायक निदेशक डॉ भोलेश जैन ने शिविर के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि शिविर में विशेषज्ञ आयुर्वेद शल्य चिकित्सकों द्वारा जटिल गुदरोगों, जैसे पाइल्स (बवासीर), फिस्टुला (भगंदर), और फीशर आदि का प्रभावी क्षारसूत्र चिकित्सा विधि से उपचार किया जाएगा।

रकुल प्रीत सिंह ने की प्लास्टिक सर्जरी कराने का दावा करने वाले चिकित्सक की आलोचना

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर खुद को चिकित्सक बताने वाले उस व्यक्ति की जमकर आलोचना की जिसने दावा किया था कि उन्होंने (रकुल प्रीत ने) प्लास्टिक सर्जरी कराई है। अभिनेत्री ने साथ ही अपने प्रशंसकों से आग्रह किया कि वे बिना तथ्यों की जांच किए ऐसे धोखेबाज लोगों के बयानों पर विश्वास न करें। डॉ. प्रशांत यादव नाम के एक व्यक्ति ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उसने अभिनेत्री की तस्वीरों और वीडियो की तुलना की। यादव के बायो के अनुसार वह बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हैं। यादव ने कहा था कि अभिनेत्री ने बोटॉक्स, फिलर्स और नाक की सर्जरी करवाई है। उन्होंने यह भी कहा था कि रकुल प्रीत सिंह खुद में आए बदलाव की जानकारी जनता से साझा करने से बचती हैं और इसके बजाय फिटनेस के बारे में बात करती हैं। अभिनेत्री ने इस वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दोबारा साझा करते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करती।

'शहज़ादी है तू दिल की' में मेरा किरदार मजबूत और आत्मनिर्भर

आशिका पादुकोण

अभिनेत्री आशिका पादुकोण का कहना है कि स्टार प्लस के शो 'शहज़ादी है तू दिल की' में उनका निभाया दीपा का किरदार मजबूत और आत्मनिर्भर है। स्टार प्लस का नया शो 'शहज़ादी है तू दिल की 'लगातार दर्शकों के दिलों को छू रहा है, और इसके असर का एक बड़ा कारण आशिका पादुकोण द्वारा निभाया गया दीपा का भावुक किरदार है। दिल टूटने, ज़िम्मेदारियों और मजबूती के बीच जूझती एक मां की भूमिका निभा रहीं आशिका ने हाल ही में अपने किरदार और उसे पर्दे पर उतारते वक्त जुड़ी इमोशनल बातों को लेकर खुलकर बात की। आशिका ने दीपा की मानसिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि उनका किरदार मजबूत और आत्मनिर्भर है, लेकिन भावनात्मक सहारे की उम्मीद में वह कहीं न कहीं नाजुक भी है।

सागरिका घाटके ने सोशल मीडिया पर शेयर की वेकेशन की खूबसूरत झलक

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान की पत्नी और अभिनेत्री सागरिका घाटके अब भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन वे अक्सर सोशल मीडिया पर जिंदगी से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं। अभिनेत्री ने सोमवार को वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर कीं। अभिनेत्री सागरिका घाटके ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वेकेशन की प्यारी यादें शेयर कीं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, 'नंगे पांव चलना, आरामदायक दिन बिताना। यह द्वीप बेहद सुंदर है। साथ ही, इसके चारों तरफ पेड़ और घने हरे पत्तों की छटा बिखरी हुई है। लैगून बिल्कुल वैसा ही है, जैसा मुझे पसंद है, शांत, साफ-सुथरा और तैरने के लिए बिल्कुल अच्छा।' अभिनेत्री ने बताया कि उनके बेटे फतेह को पानी से काफी लगाव है और वेकेशन में उसने पानी में खूब मस्ती की।

'चलो चलो हो गया', पैप्स को फिर इग्नोर कर पार्टी में पहुंचे

आर्यन खान

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एक बार फिर अपनी प्राइवेसी को लेकर सुर्खियों में हैं. सोमवार रात मुंबई में सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान के बर्थडे पार्टी में किंग खान के लाडले आर्यन पहुंचे. जहां वह पैपराजी से बचते हुए तेजी से वेन्यू में एंट्री करते नजर आए. सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे उनकी सिक्योरिटी टीम ने कैमरामैन से कहा, 'चलो चलो हो गया' और इसी बीच आर्यन कार से उतरकर सीधे वेन्यू में पहुंच गए। इस पार्टी में सलमान खान, मलाइका अरोड़ा, फरदीन खान, सुहाना खान, कार्तिक आर्यन समेत कई सितारे पहुंचे थे, लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का यह अवॉइडेंस अब सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पैपराजी ने उन्हें बार-बार आवाज लगाते रहे. लेकिन आर्यन खान एक बार भी नहीं रुके और सीधे चले गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह कोई पहली बार नहीं है जब आर्यन ने मीडिया की नजरों से दूरी बनाई है. वह अक्सर लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं और न ही पैपराजी को पोज देते हैं, न ही सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी की झलकियां शेयर करते है।

श्रद्धा कपूर ने किया धुरंधर का मूवी रिव्यू

फिल्म के निगेटिव पीआर पर दी प्रतिक्रिया

कहा- हमारी भावनाओं के साथ मत खेलिए

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म ने दुनियाभर में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार के बाद अब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी फिल्म की तारीफ की है। श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर धुरंधर देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहली स्टोरी में लिखा, 'आदित्य धर ने धुरंधर जैसी फिल्म बनाकर बहुत गलत किया। ' इसके बाद दूसरी स्टोरी में उन्होंने लिखा, 'और फिर पार्ट 2 के लिए तीन महीने इंतजार करवा रहे हैं। हमारी भावनाओं के साथ मत खेलिए, रिलीज पहले कर दीजिए। यह शानदार अनुभव था। अगर सुबह शूट नहीं होता तो मैं अभी दोबारा फिल्म देखने चली जाती। 'श्रद्धा ने आगे लिखा कि साल 2025 में हिंदी सिनेमा के लिए यह एक मजबूत दौर है। उन्होंने छावा, सैयारा और धुरंधर जैसी फिल्मों का जिक्र किया। इसके अलावा श्रद्धा कपूर ने फिल्म को लेकर हुई नेगेटिव पीआर और बनाए गए विवादों पर भी बात की। उन्होंने लिखा कि यामी गौतम को फिल्म के खिलाफ चल रही नेगेटिव पीआर पर खुलकर बोलना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद धुरंधर मजबूती से आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्म को कोई गलत ताकत नीचे नहीं खींच सकती और दर्शकों पर भरोसा है। धुरंधर एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर. माधवन अहम भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंडोर ने भी काम किया। अब धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाला है।

अचीवर्स ऑफ 2025 भारतीय मनोरंजन की परिभाषा बदलने वाले पावर परफॉर्मर्स के नामों पर डालें एक नजर

2025 भारतीय मनोरंजन की दुनिया के लिए एक बेहद खास साल रहा। इस साल कलाकारों ने हर प्लेटफॉर्म पर सफलता और कहानी कहने का तरीका बदल दिया। रिकॉर्ड तोड़ कमाई, नेशनल अवॉर्ड जीतना, नए काम की शुरुआत और समाज पर असर डालने वाले काम इन सबके जरिए इन लोगों ने सिर्फ लोगों का मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि सोच और बातचीत को भी आगे बढ़ाया। यह लिस्ट उन अलग-अलग कलाकारों को सलाम करती है जिन्होंने अपनी मेहनत, भरोसे और लगातार अच्छे काम से इस साल को यादगार बनाया और फिल्म व क्रिएटिव दुनिया पर अपनी गहरी छाप छोड़ी।

आमिर खान

आमिर खान की सितारे ज़मीन पर इस साल की उन फिल्मों में रही जिसने बेहद संवेदनशील विषय को सादगी और भावनाओं के साथ पेश किया। स्पोर्ट्स ड्रामा के ज़रिए फिल्म ने विशेष बच्चों की दुनिया और उनके संघर्ष को सामने रखा। इसमें 10 नए कलाकारों को पहली बार बड़े पर्दे पर मौका मिला और दर्शकों ने फिल्म को दिल से अपनाया, जिससे यह बॉक्स ऑफिस पर भी कामयाब रही। आमिर ने एक बार फिर यह दिखाया कि वे मनोरंजन के साथ-साथ समाज से जुड़ी कहानियों को कितनी अहमियत देते हैं। उन्होंने फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज़ किया और बाद में यूट्यूब पर लाकर एक अलग रास्ता चुना। इसी साल अगस्त 2025 में आई रजनीकांत और नागार्जुन की फिल्म कुली में आमिर खान एक खास कैमियो में भी नजर आए।

एकता कपूर

एकता कपूर ने 2025 में टीवी और डिजिटल दुनिया पर पूरी तरह अपनी पकड़ बनाए रखी। लगातार हिट शोज़ और ऊँची टीआरपी के साथ उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि इस मीडियम पर उनका दबदबा कायम है। इसी साल उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को उसके 25 साल पूरे होने पर दोबारा लॉन्च किया। यह शो न सिर्फ पुराने दर्शकों की यादें ताज़ा कर रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी कहानी से जोड़ने में सफल रहा है और शानदार प्रदर्शन कर रहा है।

फरहान अख्तर

इस साल फरहान अख्तर ने 120 बहादुर में दमदार अभिनय करने के साथ-साथ फिल्म के निर्माता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई। इस प्रोजेक्ट ने उन्हें एक बार फिर एक मजबूत अभिनेता और संवेदनशील फिल्ममेकर के रूप में साबित किया। वहीं, एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले सुपरबॉयज़ ऑफ मालेगांव, ग्राउंड ज़ीरो, सॉन्स ऑफ पैराडाइज़ और डब्बा कार्टेल जैसे प्रोजेक्ट्स सामने आए। फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर फरहान की क्रिएटिव पकड़ पूरे साल साफ नजर आई और उनका असर लगातार महसूस किया गया।

सलमान खान

इस साल सलमान खान की बड़ी फिल्म सिकंदर ईद के मौके पर रिलीज़ हुई और दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला। इसके

साथ ही वह बिग बॉस के एक और सफल सीज़न के साथ टीवी पर भी छाए रहे। फिल्मों के अलावा, उनके सामाजिक काम और इंडस्ट्री को दिया गया समर्थन भी खूब चर्चा में रहा। उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग और स्टार पावर ने अलग-अलग इलाकों में दर्शकों का भरोसा बनाए रखा और पूरे साल उनकी मौजूदगी लगातार महसूस की गई।

शाहरुख खान

इस साल शाहरुख़ खान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्हें जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे की पहली वेब सीरीज़ द बैंड्स ऑफ बॉलीवुड में एक छोटी लेकिन खास भूमिका भी निभाई। इस सीरीज़ को शाहरुख ने खुद बनाया और इसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे यह साल उनके लिए बेहद यादगार बन गया।

सोहम शाह

सोहम शाह के लिए यह साल बॉक्स ऑफिस पर खास रहा। उनकी खुद की बनाई फिल्म क्रेज़ी ने अच्छी ओपनिंग ली और दर्शकों से ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिली। इसके अलावा इस साल उनकी एक और फिल्म उफ्फ ये सियापा भी रिलीज़ हुई। साथ ही, सोहम तुम्बाड के सबसे ज्यादा इंतेज़ार किए जा रहे सीक्वल पर लगातार काम करते रहे, जिससे फैंस की उत्सुकता बनी हुई है।

विक्की कौशल

विक्की कौशल के लिए यह साल बेहद खास साबित हुआ। छावा की सफलता ने उनके करियर में एक नया मुकाम जोड़ा, जहां उनके दमदार ट्रांसफॉर्मेशन और शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी मजबूत प्रदर्शन किया।

रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना के लिए यह साल बेहद शानदार रहा। साल की शुरुआत छावा जैसी बड़ी हिट से हुई, जो उनकी लगातार तीसरी फिल्म बनी जिसने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। इसके बाद उन्होंने सिकंदर, कुबेरा, थम्मा और अपनी नई फिल्म द गर्लफ्रेंड में अलग-अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता और गहराई साबित की। फिल्मों के अलावा उन्होंने अपनी फ्रेगरेंस लाइन की ब्रांड 'डियर डायरी' भी लॉन्च की और कई बड़े ग्लोबल इवेंट्स में नजर आईं। इन सबके जरिए रश्मिका ने एक बार फिर खुद को पैन-इंडिया ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टार के तौर पर मजबूत किया।

रणवीर सिंह

रणवीर सिंह ने इस साल धुरंधर के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की। 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस फिल्म ने एक बार फिर साबित किया कि रणवीर की स्टार पावर कितनी मजबूत है और वह हर तरह के किरदार निभाने में माहिर हैं। फिल्मों के अलावा रणवीर ने बिज़नेस की दुनिया में भी कदम बढ़ाया और अपनी प्रीमियम स्पिरिट्स ब्रांड्स रंगीला (वोडका) और येलो (डिज़ाइनर व्हिस्की) लॉन्च कीं। इसके साथ ही उनके पास आने वाले समय में कई बड़ी और चर्चित फिल्में भी लाइन में हैं।

कृति सेनन

कृति सेनन के लिए 2025 एक शानदार साल साबित हुआ। इस साल उन्हें जेंडर इक्वालिटी के लिए हस्नक्ककी मानद एंबेसडर बनाया गया, जो उनके सामाजिक योगदान को भी दिखाता है। फिल्मों की बात करें तो धनुष के साथ उनकी फिल्म तेरे इश्क़ में रिलीज़ हुई, जिसे बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उनकी सफल फिल्मों की कड़ी को और मजबूत किया। अभिनय के साथ-साथ कृति ने अपने ब्यूटी और वेलनेस ब्रांड को भी आगे बढ़ाया। इस तरह 2025 में कृति सेनन ने न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान और मजबूत की।

यामी गौतम

यामी गौतम के लिए 2025 एक मजबूत और सफल साल रहा। नवंबर 2025 में रिलीज़ हुई कोर्टरूम ड्रामा हक़ में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जो ऐतिहासिक शाह बानो केस से प्रेरित थी और दर्शकों के बीच खूब सराही गई। इससे पहले फरवरी 2025 में उनकी वेब ओरिजिनल फिल्म धूम धाम रिलीज़ हुई थी, जिसे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दोनों ही प्रोजेक्ट्स की सफलता ने साबित किया कि यामी लगातार दमदार और असरदार कहानियों का हिस्सा बन रही हैं और यह साल उनके करियर के लिए एक और मजबूत पड़ाव बनकर सामने आया।

ऋषभ शेट्टी

ऋषभ शेट्टी के लिए 2025 एक शानदार साल साबित हुआ। कांतारा: चैप्टर 1 ने दुनियाभर में जबरदस्त सफलता हासिल की और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। एक अभिनेता और निर्देशक दोनों के रूप में उनके काम की खूब तारीफ हुई। नवंबर 2025 में उन्हें सरकारी हि.प्रा. शाले, कासरगोडु के लिए कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इसके अलावा, त्तक्कमेन ऑफ द ईयर अवॉर्ड्स में उन्हें सिनेमैटिक पावरहाउस के सम्मान से भी नवाजा गया, जिसने उनके प्रभावशाली सफर को और मजबूती दी।

विक्रांत मैसी

विक्रांत मैसी के लिए 2025 बेहद खास और यादगार साल रहा। उन्होंने 12वीं फेल के लिए अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड (बेस्ट एक्टर) जीतकर अपने करियर की बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा, सेक्टर 36 के लिए उन्हें दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड भी मिला। इतना ही नहीं, उन्हें ग्लोबल पीस ऑनर्स में भी सम्मानित किया गया। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने भी अडानी ग्री टॉक्स इवेंट में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने पर बधाई दी और सम्मानित किया। यह साल विक्रांत मैसी के लिए मेहनत, पहचान और सफलता का प्रतीक बनकर सामने आया।

रकुल प्रीत सिंह

2025 में हमने देखा कि रकुल प्रीत सिंह ने मेरे हसबैंड की बीवी और दे दे प्यार दे 2 जैसी फिल्मों के साथ एक मजबूत साल दिया। इन दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहना मिली और दर्शकों ने भी उन्हें भरपूर प्यार दिया। इसी साल उन्हें 'वर्सेटाइल स्टार' और 'प्योर प्रेज़ेंस ऑफ द ईयर' जैसे अवॉर्ड्स से भी सम्मानित किया गया, जो इंडस्ट्री में उनकी बढ़ती पकड़, आकर्षण और प्रभाव को साफ तौर पर दिखाता है।

2025 के अंत तक आते-आते यह साफ हो गया कि ये सभी शख्सियतें सिर्फ बड़ी उपलब्धियां हासिल करने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि अपनी ईमानदार सोच, साहसी फैसलों और कड़ी मेहनत से अलग पहचान बनाने में भी सफल रहीं। इनके काम ने मनोरंजन की पारंपरिक सीमाओं को आगे बढ़ाया, नई और असरदार कहानियों को सामने लाया और एक बार फिर यह भरोसा दिलाया कि सिनेमा लोगों को जोड़ने, भावनाओं को छूने और सोच बदलने की ताकत रखता है। ये सभी मिलकर उस नई इंडस्ट्री की तस्वीर पेश करते हैं जो बेखौफ है, नवाचार को अपनाती है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा रही है।

(साभार एजेंसी)

दुबई एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025:

भारतीय खिलाड़ियों ने जीते 8 स्वर्ण पदक

नई दिल्ली, एजेंसी। दुबई में 7 से 14 दिसंबर तक आयोजित युवा एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 मेडल जीते। इसमें 8 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक थे। भारत की तरफ से जतिन आजाद ने एसयू5 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते।

पहले उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता और फिर शिवम यादव के साथ पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। जतिन आजाद ने कहा, 'मैं सभी चैंपियनशिप में खेलना चाहता हूं, और ज्यादा अनुभव और एक्सपोजर हासिल करना चाहता हूं। मुझे पता है कि मुझे लॉस एंजिल्स 28 पैरालिंपिक के लिए चुना जाएगा। 'आजाद ने कहा, 'हर किसी में शुरू करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन बस खेलो, अपना बेस्ट दो, अच्छी ट्रेनिंग करो, नतीजे मिलेंगे।'

दुबई 2025 सभी भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए पहला एशिया युवा खेल था। इस इवेंट ने खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच उपलब्ध कराया है। लॉस एंजिल्स 2028 पैरालिंपिक के पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए यह एक अहम इवेंट था। भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार अच्छा कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों को जोरदार टक्कर दे रहे हैं और पदक जीत रहे हैं।

ऐसे में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों का दुबई में शानदार प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन की मजबूती और गहराई को दिखाता है। एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने के बाद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि लॉस एंजिल्स 2028 पैरालिंपिक में भी बैडमिंटन में भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।

हर्षित चौधरी ने भी स्वर्ण पदक जीता।

हर्षित ने कहा, 'मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम हर चीज के लिए तैयार थे। मैं और मेरे साझीदार सकारात्मक रहे।

अंडर 19 एशिया कप :

अभिज्ञान कुंडू ने ठोका दोहरा शतक, अंडर 19 एशिया कप में रचा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। अंडर 19 एशिया कप में भारत के लिए ही नहीं किसी भी टीम के बल्लेबाज के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड अब टूट चुका है।

भारत के अभिज्ञान कुंडू ने मंगलवार को मलेशिया के खिलाफ 209 रन की ऐतिहासिक नाबाद पारी खेली और सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। उन्होंने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले पाकिस्तान के समीर मिन्हास (177) और भारत के वैभव सूर्यवंशी (171) को पीछे छोड़ा। वहीं वह अंडर 19 एशिया कप के 36 साल के इतिहास में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने। उन्होंने अपनी 125 गेंद की पारी में नाबाद 209 रन बनाए जिसमें 17 चौके और 9 छक्के शामिल थे।

वह इसी के साथ मौजूदा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ओवरऑल रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। उन्होंने पाकिस्तान के समीर मिन्हास (220) को पीछे छोड़ा।

पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेट कप्तान अर्जुन रणतुंगा की होगी गिरफ्तारी

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका को वर्ष 1996 में क्रिकेट विश्व कप जिताने वाली टीम के कप्तान और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री अर्जुन रणतुंगा को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। यह जानकारी बीबीसी न्यूज़ सिंहला के हवाले से सामने आई है। सोमवार को कोलंबो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (सीपीसी) के पूर्व अध्यक्ष और अर्जुन रणतुंगा के भाई धम्मिका रणतुंगा को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। धम्मिका रणतुंगा को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच के लिए गठित आयोग ने गिरफ्तार किया था। जांच आयोग ने अदालत को बताया कि इस मामले में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री अर्जुन रणतुंगा को संदिग्ध के रूप में पहचाना गया है और उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा। धम्मिका रणतुंगा पर आरोप है कि उन्होंने 2017-2018 के दौरान ईंधन की खरीद के लिए जारी तीन दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) टेंडरों को रद्द कर दिया और उनकी जगह अधिक कीमत वाले स्थानीय टेंडर लागू किए।

कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में KKR ने खरीदा; स्टार्क और कमिंस का रिकॉर्ड टूटा, बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी

आईपीएल ऑक्शन 2026

नई दिल्ली, एजेंसी। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन पर ताबड़तोड़ बोली लगी है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर के लिए पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जंग हुई। उसके बाद सीएसके की इसमें एंट्री हुई। बाद में बाजी केकेआर ने मारी और ग्रीन को 25.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ा। कैमरन ग्रीन अब आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और सबसे महंगे विदेशी बन गए हैं।

कैमरन ग्रीन की इस बोली से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड टूट गया है। कमिंस को आईपीएल 2024 में हुए ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा था। वहीं स्टार्क पर केकेआर ने ही 2024 ऑक्शन में 24.75 करोड़ की बोली लगाई थी। अब केकेआर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और कैमरन ग्रीन पर करोड़ों की बारिश हुई।

नहीं मिलेंगे 18 करोड़ से ज्यादा रुपए: गौरतलब है कि आईपीएल 2026 ऑक्शन के लिए मैक्सिमम फीस नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ रुपये से ज्यादा का पेमेंट नहीं किया जा सकता, जो 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए सबसे बड़ा स्लैब था। अगर बोली 18 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है तो अतिरिक्त पैसे का इस्तेमाल बीसीसीआई खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए करेगा। यह नियम भारतीय खिलाड़ियों पर लागू नहीं होगा।

आईपीएल इतिहास के पांच सबसे महंगे खिलाड़ी

ऋषभ पंत- 27 करोड़ (लखनऊ सुपर जायंट्स)

श्रेयस अय्यर- 26.75 करोड़ (पंजाब किंग्स)

कैमरन ग्रीन- 25.20 करोड़ (केकेआर), 2025 मिनी ऑक्शन

मिचेल स्टार्क- 24.75 करोड़ (कोलकाता नाइट राइडर्स)

वेंकटेश अय्यर- 23.75 करोड़ (कोलकाता नाइट राइडर्स)

एशेज :

बॉन्डी बीच गोलीबारी की घटना के बाद एडिलेड टेस्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

एडिलेड, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच बुधवार से एडिलेड ओवल में खेला जाना है। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का ऐलान किया है। यह फैसला सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद लिया गया है।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के स्टेट प्रीमियर पीटर मलिनाउस्कस ने बताया कि स्टेडियम के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा नियम लागू किए जाएंगे। इनमें राइफल से लैस पुलिसकर्मियों की तैनाती भी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि सिडनी की घटना को देखते हुए यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है और फिलहाल सतर्क रहना जरूरी है। डेली मेल के हवाले से मलिनाउस्कस ने कहा, 'सिडनी में हुई घटनाओं को देखते हुए, एडिलेड ओवल में अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। यह सिर्फ़ एहतियात के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन यह सही है कि इस समय हम ज़्यादा सतर्क रहें। 'बॉन्डी बीच पर यह हमला एक यहूदी धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें दो लोगों ने गोलीबारी की। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। हमलावरों को जल्द ही पकड़ लिया गया, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में गंभीर हालत में है। इस घटना के बाद दक्षिण ऑस्ट्रेलिया पुलिस आयुक्त ग्रांट स्टीवंस ने बताया कि मैच के दौरान एडिलेड ओवल के आसपास विशेष रूप से प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया है कि फिलहाल क्रिकेट मैच या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर किसी बड़े खतरे के संकेत नहीं मिले हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त बयान जारी कर इस हमले पर गहरा दुख जताया है और पीड़ितों व उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सम्मान के तौर पर मैच शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन रखा जाएगा और दोनों टीमों के खिलाड़ी काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरेंगे। पांच मैचों की इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया फिलहाल 2-0 से आगे है और तीसरा टेस्ट जीतकर एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखने की कोशिश करेगा।

इंडिया-दक्षिण अफ्रीका टी-20:

जसप्रीत बुमराह ने बीच में ही क्यों छोड़ दी 20 सीरीज ?

नई दिल्ली, एजेंसी। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की धर्मशाला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से अनुपस्थिति ने तुरंत सवाल खड़े कर दिए, खासकर तब जब वह पांच मैचों की करीबी श्रृंखला में भारत की गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ माने जाते हैं. सीनियर तेज गेंदबाज रविवार को मैदान पर नहीं उतरे, जिससे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले के लिए भारत को अपने तेज गेंदबाजी संसाधनों में बदलाव करना पड़ा. एक रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह को घर लौटना पड़ा क्योंकि उनके एक बेहद करीबी पारिवारिक सदस्य फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. स्थिति ऐसी थी कि उनकी तत्काल मौजूदगी जरूरी हो गई, और पूरा ध्यान इस निजी आपात स्थिति से निपटने पर केंद्रित रहा. नाम न बताने की शर्त पर बात करने वाले बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि बुमराह की श्रृंखला में वापसी पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगी कि हालात कैसे आगे बढ़ते हैं.

बुमराह की गैरमौजूदगी के बावजूद भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली. कटक में पहला टी20 जीतने के बाद भारत को मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे मैच में 51 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे धर्मशाला का मुकाबला बेहद अहम बन गया था. मेजबान टीम ने अनुशासित ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर शानदार वापसी की, दक्षिण अफ्रीका को 117 रन पर रोकने के बाद लक्ष्य को सिर्फ 15.5 ओवर में सात विकेट से हासिल कर लिया. भारत के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारने के बाद शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली.

सूर्या ने टॉस के बाद दी जानकारी

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने स्पष्ट किया कि बुमराह व्यक्तिगत कारणों से चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे, जबकि अक्षर पटेल भी बीमार पड़ने के कारण मैच से बाहर रहे. बाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने पुष्टि की कि बुमराह एक पारिवारिक मामले के चलते मुंबई लौट गए हैं, जिसके कारण उन्हें श्रृंखला के बीच में ही टीम छोड़नी पड़ी.

टी20 सीरीजः साउथ अफ्रीका के खिलाफ आखिरी 2 मुकाबलों से अक्षर पटेल बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल बीमारी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के शेष 2 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। हालांकि, अक्षर लखनऊ में टीम के साथ हैं, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। पुरुष चयन समिति ने लखनऊ और अहमदाबाद में होने वाले टी20 मुकाबलों के लिए शाहबाज अहमद को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में खेले गए सीरीज के पहले मैच को 101 रन से अपने नाम किया था। इस मुकाबले में मेजबान टीम ने 6 विकेट खोकर 175 रन बनाने के बाद मेहमान टीम को 12.3 ओवरों में 74 रन पर समेट दिया। अगले मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 213 रन बनाए, लेकिन टीम इंडिया 19.1 ओवरों में महज 162 रन पर सिमट गई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने 51 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। धर्मशाला में सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। साउथ अफ्रीकी टीम को 117 रन पर समेटने के बाद भारत ने 15.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

शेफाली वर्मा ने जीता आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को नवंबर 2025 के लिए 'आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया है। शेफाली वर्मा ने बीते महीने संपन्न हुए महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ यादगार पारी खेली थी। शेफाली ने थाईलैंड की थिपत्चा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा को पछाड़कर अपना पहला 'प्लेयर ऑफ द मंथ' अवॉर्ड जीता है। शेफाली वर्मा को महिला वनडे विश्व कप में चोटिल प्रतिका रावल के स्थान पर टीम में शामिल किया गया था। शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में महज 10 रन की पारी खेली, जिसके बाद खिताबी मुकाबले में 78 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 7 चौकों के साथ 87 रन बनाए।

यह वर्ल्ड कप फाइनल में किसी भारतीय महिला ओपनर का सबसे बड़ा स्कोर है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। आईसीसी की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में शेफाली ने कहा, 'मेरा पहला आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का अनुभव वैसा नहीं रहा जैसा मैंने सोचा था, लेकिन यह सफर उससे कहीं बेहतर तरीके से खत्म हुआ जैसा मैंने कभी सोचा या कल्पना की थी।

मैं शुक्रगुजार हूं कि फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे पाई और पहली बार वर्ल्ड कप जीतने और घरेलू दर्शकों के सामने इतिहास रचने का हिस्सा बन पाई। उन्होंने कहा, 'मुझे नवंबर के लिए 'महिला प्लेयर ऑफ द मंथ' चुने जाने पर बहुत गर्व है। मैं यह अवॉर्ड अपनी टीम के साथियों, कोच, परिवार और उन सभी को समर्पित करती हूं जिन्होंने अब तक यात्रा में मेरा साथ दिया है। हम एक टीम के तौर पर जीतते और हारते हैं। यह बात इस अवॉर्ड पर भी लागू होती है।

खराब फॉर्म के बाद शेफाली वर्मा ने भारतीय महिला टीम से अपनी जगह गंवा दी थी, लेकिन विश्व कप में उन्हें गोल्डन चांस मिल गया। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए शेफाली वर्मा ने आलोचकों को करारा जवाब दिया। शेफाली अब 21 दिसंबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगी।

विभिन्न क्षेत्रों में जॉर्डन के साथ सहयोग का सार्थक विस्तार हुआ है : प्रधानमंत्री मोदी

» अम्मान, भाषा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को जॉर्डन की अपनी यात्रा के ठोस नतीजों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन, संस्कृति और डिजिटल नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग का सार्थक विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी की चार दिवसीय तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। भारत और जॉर्डन ने सोमवार को द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता को बड़ा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग (जुड़वां) व्यवस्था के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मंगलवार को सोशल मीडिया पर किए गए कई पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ए उपलब्धियां भारत-जॉर्डन साझेदारी के सार्थक विस्तार को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि नई और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग स्वच्छ विकास, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु जिम्मेदारी के प्रति साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संसाधन प्रबंधन और विकास में सहयोग से दोनों देश संरक्षण, दक्षता और तकनीक से जुड़ी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा कर सकेंगे, जिससे दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सांस्कृतिक सहयोग पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रा और एलोरा के बीच ट्विनिंग समझौता विरासत संरक्षण, पर्यटन और शैक्षणिक आदान-प्रदान के नए अवसर खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2025-2029 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के नवीनीकरण से दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के डिजिटल नवाचारों को जॉर्डन के साथ साझा करने से वहां के डिजिटल परिवर्तन को समर्थन मिलेगा और समावेशी शासन को बढ़ावा मिलेगा। मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय में सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने बताया कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त किया और आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कट्टरपंथ उन्मूलन के क्षेत्र में शाह अब्दुल्ला के नेतृत्वकारी प्रयासों की सराहना की। मोदी की जॉर्डन यात्रा भारत और अरब देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। यह प्रधानमंत्री की जॉर्डन की पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले, फरवरी 2018 में वह फलस्तीन जाते समय जॉर्डन से होकर गुजरे थे। भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, जिसमें नई दिल्ली अम्मान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

भारत का पाकिस्तान पर करारा तंज

प्रधानमंत्री को कैद करना ही है लोगों की इच्छा का सम्मान

» संयुक्त राष्ट्र, भाषा।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कड़े शब्दों में पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे की आलोचना करते हुए कहा कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का अनूठा तरीका यह है कि वह एक निर्वाचित प्रधानमंत्री को जेल में डाल देता है और अपने सेना प्रमुख को आजीवन कानूनी सुरक्षा दे देता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वतनेनी ने सोमवार को सुरक्षा परिषद में शांति के लिए नेतृत्व विषय पर हुई खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद द्वारा जम्मू कश्मीर और सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाए जाने के बाद कड़ा जवाब दिया। हरीश ने कहा, आज की खुली बहस में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अनुचित उल्लेख भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित है।

एक गैर-स्थाई सुरक्षा परिषद सदस्य, जो अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के हर मंच और हर बैठक का दुरुपयोग करता है, उससे अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उसके सभी रूपों और स्वरूपों में पूरी ताकत से मुकाबला करेगा। भारत ने पाकिस्तानी दूत के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र चार्टर, प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हरीश ने कहा, पाकिस्तान के पास अपने लोगों की इच्छा का सम्मान करने का बेशक एक अनूठा तरीका है - एक प्रधानमंत्री को जेल में डालना, सत्ता में रहे राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाना और 27वें संशोधन के जरिए सशस्त्र बलों द्वारा एक संवैधानिक तख्तापलट की राह बनाने की अनुमति देना तथा अपने सेना प्रमुख को आजीवन सुरक्षा देना। पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं और खबरों के अनुसार उन्हें लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया है। यातना संबंधी मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत ऐलिस जिल एडवर्ड्स ने पाकिस्तान सरकार से खान को अमानवीय और अपमानजनक परिस्थितियों में हिरासत में रखे जाने की खबरों पर तत्काल कार्वाई करने का आग्रह किया है और चेतावनी दी है कि ये यातना या अन्य दुर्व्यवहार की श्रेणी में आ सकती हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में पारित 27वां संवैधानिक संशोधन रक्षाध्यक्ष और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को किसी भी कानूनी कार्वाई से आजीवन सुरक्षा देता है। हरीश ने दोहराया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने 65 वर्ष पहले सिंधु जल संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से की थी। हरीश ने कहा, इन साढ़े छह दशकों में पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध थोपकर और हजारों आतंकवादी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, पिछले चार दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों में हजारों भारतीयों की जान गई है।

स्वयं वाहन चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को संग्रहालय लेकर गए जॉर्डन के युवराज

अम्मान, भाषा। भारत और जॉर्डन के संबंधों में गर्मजोशी को दर्शाते हुए अरब देश के युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्वयं वाहन चलाकर जॉर्डन संग्रहालय लेकर गए। युवराज पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि वह संग्रहालय में जॉर्डन के इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दिखाने के लिए अल-हुसैन के प्रति आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने युवराज के साथ विस्तृत बातचीत की है तथा जॉर्डन की प्रगति के प्रति उनका जुनून स्पष्ट रूप से नजर आया। मोदी ने कहा कि युवा विकास, खेल, अंतरिक्ष, नवाचार और दिव्यांगजनों के कल्याण को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में उनका योगदान वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने अल-हुसैन को जॉर्डन के विकास पथ को मजबूत करने के उनके प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं दीं। मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे।

प्रधानमंत्री का अगले पांच वर्ष में भारत-जॉर्डन व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डॉलर करने का प्रस्ताव

अम्मान, भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्ष में दोगुना करके पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का मंगलवार को प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने जॉर्डन की कंपनियों को देश की उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आमंत्रित किया। मोदी सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। वह किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। जॉर्डन, प्रधानमंत्री की चार दिवसीय तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है। इसके बाद वह इथियोपिया और ओमान भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने यहां भारत-जॉर्डन व्यापार मंच को मंगलवार को संबोधित किया। इस सम्मेलन में युवराज हुसैन और जॉर्डन के व्यापार एवं उद्योग मंत्री तथा निवेश मंत्री भी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के महत्व को स्वीकार किया। साथ ही दोनों पक्षों के उद्योगपतियों से इस क्षमता एवं अवसरों को वृद्धि और समृद्धि में बदलने का आह्वान किया। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि जॉर्डन के मुक्त व्यापार समझौतों और भारत की आर्थिक शक्ति को मिलाकर दक्षिण एशिया एवं पश्चिम एशिया तथा उससे परे एक आर्थिक गलियारा बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जॉर्डन से इथियोपिया रवाना

अम्मान, भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया के लिए रवाना हुए। जॉर्डन के युवराज अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने प्रधानमंत्री मोदी को हवाई अड्डे तक पहुंचाया और उन्हें विदाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न हुई। भारत-जॉर्डन के सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाते हुए, युवराज अल-हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हवाई अड्डे तक छोड़ने गए। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में इथियोपिया के लिए रवाना हो गए हैं। इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे और लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत की यात्रा पर अपने विचार साझा करेंगे। साथ ही भारत-इथियोपिया साझेदारी ग्लोबल साउथ के लिए क्या मायने ला सकती है इस पर भी विचार व्यक्त करेंगे। मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से भी बातचीत करेंगे और प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर सोमवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। भारत और जॉर्डन के बीच सोमवार को कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों और मित्रता को व्यापक विस्तार देना है। इथोपिया से, मोदी अपने तीन देशों के दौरे के तीसरे चरण में ओमान जाएंगे।

शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ वार्ता से भारत जॉर्डन साझेदारी हुई मजबूतः मोदी

अम्मान, भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ उनकी वार्ता ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत सहयोग समेत प्रमुख क्षेत्रों में भारत-जॉर्डन साझेदारी को मजबूत किया है। दो दिवसीय यात्रा के अंत में मोदी ने कहा, मेरी जॉर्डन यात्रा बेहद फलदाई रही है। उन्होंने शाह अब्दुल्ला द्वितीय और जॉर्डन के लोगों को उनकी असाधारण मित्रता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हमारी चर्चाओं ने नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विरासत सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-जॉर्डन साझेदारी को मजबूत किया है। हमने मिलकर जो परिणाम हासिल किए हैं, वे हमारे नागरिकों के लिए प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेंगे। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता से पहले सोमवार को मोदी ने हुसैनीया महल में शाह अब्दुल्ला द्वितीय के साथ आमने-सामने बैठक की। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों की सराहना की, जिसकी पहचान आपसी विश्वास, सौहार्द और सद्भावना है। इसमें कहा गया है, दोनों ने भारत-जॉर्डन के बहुआयामी संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन किया है, जो राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और शिक्षा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट सहयोग की भी सराहना की। अपनी बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में विश्वसनीय साझेदार के रूप में आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और एक साथ खड़े रहने पर सहमति व्यक्त की।

बॉण्डी बीच पर हुई गोलीबारी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थीः पुलिस

» मेलबर्न, भाषा।

ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉण्डी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान सरेआम गोलीबारी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक आतंकवादी हमला था। ऑस्ट्रेलिया की संघीय पुलिस आयुक्त क्रिसी बैरेट ने मंगलवार को यह बात कही। इस हमले में 15 लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया है कि संदिग्ध हमलावर पिता और पुत्र थे। उन्होंने बताया है कि एक हमलावर (50) को पुलिस ने मार गिराया जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा घायल हो गया और अस्पताल में उसका उपचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो हमलावर मारा गया उसकी पहचान अधिकारियों ने साजिद अकरम के रूप में की है।

मंगलवार को नेताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता में अधिकारियों ने पहली बार संदिग्धों की विचारधाराओं के बारे में पुष्टि की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ए टिप्पणियां प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित थीं, जिनमें जब्त किए गए वाहन में इस्लामिक स्टेट के झंडे मिलना भी शामिल है। इस हमले में घायल हुए 25 लोग अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं जिनमें से 10 की हालत गंभीर है।अल्बनीज़ ने बंदूकों तक पहुंच को और प्रतिबंधित करने की योजनाओं की घोषणा की, जिसका एक कारण यह सामने आना भी शामिल था कि बड़े संदिग्ध ने अपने छह हथियारों का जखीरा कानूनी रूप से जमा किया था। न्यू साउथ वेल्स प्रांत के पुलिस आयुक्त माल लैन्योन ने बताया कि संदिग्ध पिछले महीने फिलीपींस गए थे।

बॉण्डी बीच पर हुई गोलीबारी में घायल लोगों में तीन भारतीय

मेलबर्न, भाषा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉण्डी बीच पर हुए आतंकवादी हमले में घायल हुए 40 लोगों में तीन भारतीय छात्र भी शामिल हैं। स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई। ऑस्ट्रेलिया टुडे समाचार पोर्टल के मुताबिक घायल तीन भारतीय छात्रों में से दो का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने रविवार के हमले में घायल हुए भारतीय छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। खबर में कहा गया कि गोलीबारी के दौरान भारतीय छात्र घायल हो गए और उनकी सटीक स्थिति की अभी तक औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि 24 वर्षीय नवीद अकरम और उसके 50 वर्षीय पिता ने यहूदी त्योहार हनुक्का मना रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी। उन्होंने बताया कि इस हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। घायलों में से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दो घायल पुलिस अधिकारियों की हालत गंभीर लेकिन स्थिर है।

न्यूज ब्रीफ

श्रीलंका में चक्रवात प्रभावित प्रांतों के 600 से अधिक विद्यालय तीसरे सत्र के लिए नहीं खुलेंगे

» कोलंबो, भाषा।

श्रीलंका में चक्रवात प्रभावित तीन प्रांतों के 600 से अधिक विद्यालय (शैक्षणिक सत्र की) तीसरे सत्र के लिए नहीं खुलेंगे और विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। न्यूजफर्स्ट लंका पोर्टल के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक वर्ष 2025 की तीसरी सत्र के लिए छठी से 10वीं तक की कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित करने से परहेज करें। श्रीलंका में मुख्य रूप से सरकारी शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष को तीन सत्रों में विभाजित किया जाता है। हालांकि हर शिक्षण संस्थान इसका पालन नहीं करता है। शिक्षा मंत्रालय के सचिव नलका कलुवेवा ने कहा, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम 640 विद्यालय बंद रहेंगे।

हमने क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे विद्यार्थियों को बिना सत्र परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दें। शिक्षा उपमंत्री मधुरा सेनेविरत्ने ने कहा कि वैसे तो विद्यालयों को मंगलवार को फिर से खोलने की योजना थी, लेकिन उन्हें फिर से खोलने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रांतीय और जिला अधिकारियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस बीच, राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोमवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपदा से सबसे अधिक प्रभावित मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण के लिए एक योजना बनाने की दिशा में काम कर रही है। दिसानायके ने कहा, हमने इन क्षेत्रों में 15,000 ऐसे घरों की पहचान की है जो खतरे में हैं। अगले साल के अंत तक, हम उनके लिए 8000 नए घरों का निर्माण पूरा कर लेंगे।

सैन फ्रांसिस्को में केबल कार अचानक रुकी, 15 लोग घायल

» सैन फ्रांसिस्को, भाषा।

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोमवार को एक केबल कार के अचानक रुक जाने से उसमें सवार कम से कम 15 लोग घायल हो गए। सैन फ्रांसिस्को के अग्निशमन विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घायलों में से दो को ज्यादा चोटें आईं, जिसके चलते उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जबकि 11 अन्य को मामूली दर्द और खिंचाव की शिकायत थी, जिसके मद्देनजर उन्हें मौके पर ही जरूरी उपचार प्रदान किया गया।

केबल कार का संचालन करने वाली सैन फ्रांसिस्को नगर परिवहन एजेंसी (एसएफएमटीए) ने कहा कि वह घटना की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। हालांकि, एजेंसी ने केबल कार के अचानक रुक जाने के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की। एसएफएमटीए ने एक बयान में कहा, केबल कार से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम घटना की गहन जांच करेंगे।

ट्रंप ने फेंटानिल को सामूहिक विनाश का हथियार करार देने वाले कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए

» वाशिंगटन, भाषा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेंटानिल को सामूहिक विनाश का हथियार करार देने वाले कार्यकारी आदेश पर सोमवार को दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस (अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यालय) में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन, व्हाइट हाउस में सीमा से जुड़े मामलों के प्रमुख टॉम होमन और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रशासन फेंटानिल को आधिकारिक तौर पर सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, जो वास्तव में वही है। कोई भी बम वह काम नहीं कर सकता, जो यह (फेंटानिल) कर रहा है।

हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि नए कार्यकारी आदेश के अमल में आने के फेंटानिल की लत के शिकार लोगों और इसकी तस्करी में शामिल अपराधियों के लिए क्या मायने होंगे तथा इससे ट्रंप प्रशासन की नीति में क्या बदलाव आएगा। सामूहिक विनाश के हथियार शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर परमाणु, जैविक, रासायनिक या साइबर खतरों के लिए किया जाता है, जो किसी आबादी, बुनियादी ढांचे या पर्यावरण को भारी एवं स्थाई नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इराक पर अमेरिका के आक्रमण के बाद वाशिंगटन के सियासी गलियारों में इस शब्द पर जमकर बहस हुई है। कार्यकारी आदेश में विदेश और वित्त विभाग को फेंटानिल की तस्करी में शामिल वित्तीय संस्थानों और समूहों पर प्रतिबंध लगाने तथा उनकी संपत्तियां जब्त करने का निर्देश दिया गया है। इसमें फेंटानिल सहित विभिन्न मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मुद्दों पर पेंटागन (अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय) और न्याय विभाग के बीच अधिक सहयोग का आह्वान भी किया गया है। आदेश में गृह सुरक्षा मंत्री से उन खुफिया संसाधनों की मदद से फेंटानिल की तस्करी में शामिल गिरोहों की पहचान करने को कहा गया है, जिनका इस्तेमाल सामूहिक विनाश के अन्य हथियारों का पता लगाने के लिए किया जाता रहा है। इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने साल की शुरुआत में कुछ मादक पदार्थ तस्करी गिरोहों को आतंकवादी समूहों के रूप में नामित किया था। इस कदम से सशस्त्र बलों और घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अधिक समन्वय का मार्ग प्रशस्त हुआ था, लेकिन कानूनी विश्लेषकों ने इसके दायरे और वैधता पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन गांजे को भी एक बार फिर कम खतरनाक मादक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रहा है।

सिडनी के ताइक्कांडो प्रशिक्षक को छात्र और उसके माता-पिता की हत्या के जुर्म में उम्रकैद

सिडनी, भाषा। ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने सिडनी के ताइक्कांडो प्रशिक्षक को सात वर्षीय छात्र और उसके माता-पिता की हत्या के जुर्म में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति इयान हैरिसन ने कहा कि दोषी 51 वर्षीय क्वांग क्युंग यू को कभी परोल नहीं मिलेगी। न्यायाधीश हैरिसन ने कहा कि यू को बच्चे परिवार की आर्थिक सफलता से जो ईर्ष्या महसूस हुई, उसी से प्रेरित होकर उसने यह कदम उठाया। न्यायाधीश ने फैसले में कहा, मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि इन अपराधों को अंजाम देने में संलिप्तता का स्तर इतना चरम था कि प्रतिशोध, सजा, सामुदायिक सुरक्षा और निवारण के संबंध में सामुदायिक हित को केवल आजीवन कारावास की सजा देकर ही पूरा किया जा सकता है। पिछले साल फरवरी में बच्चे और उसके माता-पिता की हत्या कर दी गई थी। राज्य के कानून के तहत अपराध के शिकार बच्चों की पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है। यू और सभी पीड़ित दक्षिण कोरिया में पैदा हुए थे। यू ने अदालत में पिछली बार पेशी में तीनों हत्याओं का जुर्म कबूल कर लिया था। यू ने पश्चिमी सिडनी स्थित अपने लायंस ताइक्कांडो और मार्शल आर्ट्स अकादमी में बच्चे और उसकी 41 वर्षीय मां की गला दबाकर हत्या कर दी। उस समय यू पर हजारों डॉलर का कर्ज था और अकादमी का किराया भी बकाया था। हत्या के बाद उसने बच्चे की मां की एप्पल वॉच ले ली और उनकी लग्जरी बीएमडब्ल्यू कार से परिवार के घर गया, जहां उसने लड़के के 39 वर्षीय पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि यू बचपन से ही अपने माता-पिता और दक्षिण कोरियाई संस्कृति से सफलता के स्तर के बारे में अवास्तविक अपेक्षाओं के बोझ तले दबा हुआ था।

भारत और इजराइल ने सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार किया

जयशंकर दो दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे, शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे

» यरूशलम, भाषा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल की दो दिवसीय यात्रा के तहत मंगलवार को तेल अवीव पहुंचे, जहां वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भारत के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां की जा रही हैं। नेतन्याहू ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की थी, जिसके बाद इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह अपने भारतीय समकक्ष से जल्द मुलाकात करेंगे।

इजराइल यात्रा के दौरान जयशंकर का राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिदोन सार से मिलने का कार्यक्रम है। यरूशलम में एक सूत्र ने कहा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के मकसद से चर्चा द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित होगी। जयशंकर अबू धाबी से तेल अवीव पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित सर बानी यस फोरम में हिस्सा लिया था। अबू धाबी में वह 15 दिसंबर को आयोजित भारत-यूएई संयुक्त आयोग की 16वीं बैठक और भारत-यूएई रणनीतिक संवाद के 5वें दौर में भी शामिल हुए थे। नेतन्याहू की बहुप्रतीक्षित भारत यात्रा से दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की एक श्रृंखला शुरू होने की उम्मीद है। इजराइल के पर्यटन मंत्री हैम काट्ज, उद्योग मंत्री नीर बरकत, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मंत्री एवी डिक्टर और वित्त मंत्री बेजेलल स्मोट्रिच ने साल की शुरुआत में भारत की यात्रा की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को गति मिली थी। सितंबर में स्मोट्रिच की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने एक द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद पिछले महीने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की इजराइल यात्रा के दौरान प्रस्तावित एफटीए के लिए दोनों देशों के बीच संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर दस्तखत हुए थे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने पिछले महीने रक्षा, औद्योगिक और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे सह-विकास और सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को साझा करना संभव हो सकेगा। भारत और इजराइल ने सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार किया है, जिसमें फिल्म समारोहों और नृत्य कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही फिल्म निर्माताओं का आदान-प्रदान शामिल है, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करना है। सोमवार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और तेल अवीव विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत संस्थान में एक भारत पीठ की स्थापना की जाएगी।

मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिंग सेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार्यालय 4312 मोहल्ला नायकों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, नाहरबाड़ा, रामगंज, जयपुर से प्रकाशित। संपादक मुन्ना खान मों. 08058969180 कार्यालय फोन- 0141-2609886